



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-11042026-271694
CG-DL-W-11042026-271694

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 10] नई दिल्ली, मार्च 15—मार्च 21, 2026, शनिवार/ फाल्गुन 24—फाल्गुन 30, 1947
No. 10] NEW DELHI, MARCH 15—MARCH 21, 2026, SATURDAY/ PHALGUNA 24—PHALGUNA 30, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026

का.आ. 328.—केन्द्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, राजस्व विभाग के केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन निम्नलिखित कार्यालयों, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है।

क्रम सं.	कार्यालय का नाम
1.	केंद्रीय माल और सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर आयुक्तालय (मुख्यालय)
2.	केंद्रीय माल और सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मेहसाना मण्डल, गांधीनगर आयुक्तालय
3.	केंद्रीय माल और सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पालनपुर मण्डल, गांधीनगर आयुक्तालय

4.	केंद्रीय माल और सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कडी मण्डल, गांधीनगर आयुक्तालय
5.	केंद्रीय माल और सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कलोल मण्डल, गांधीनगर आयुक्तालय
6.	केंद्रीय माल और सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर मण्डल, गांधीनगर आयुक्तालय
7.	केंद्रीय माल और सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, हिम्मतनगर मण्डल, गांधीनगर आयुक्तालय
8.	आयुक्त (अपील) का कार्यालय, केंद्रीय माल और सेवा कर, अहमदाबाद
9.	आयुक्त का कार्यालय, केंद्रीय माल और सेवा कर आयुक्तालय, पंचकूला

[फा. सं. ई-11017/3/2017-हिन्दी-2-अधिसूचना]

प्रीति सेलारे, उप निदेशक (रा.भा.)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)**

New Delhi, the 16th March, 2026

S.O. 328.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government, hereby notifies, the following offices under Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue where more than 80% staff has acquired the working knowledge of Hindi.

S. No.	Name of the Office
1.	Central Goods and Services Tax and Central Excise, Gandhinagar Commissionerate (Headquarters)
2.	Central Goods and Services Tax and Central Excise, Mehsana Division, Gandhinagar Commissionerate
3.	Central Goods and Services Tax and Central Excise, Palanpur Division, Gandhinagar Commissionerate
4.	Central Goods and Services Tax and Central Excise, Kadi Division, Gandhinagar Commissionerate
5.	Central Goods and Services Tax and Central Excise, Kalol Division, Gandhinagar Commissionerate
6.	Central Goods and Services Tax and Central Excise, Gandhinagar Division, Gandhinagar Commissionerate
7.	Central Goods and Services Tax and Central Excise, Himmat Nagar Division, Gandhinagar Commissionerate
8.	Office of the Commissioner (Appeals), Central Goods and Services Tax Appeal Commissionerate, Ahmedabad
9.	Office of the Commissioner, Central Goods and Services Tax Commissionerate, Panchkula.

[F. No. E-11017/3/2017- Hindi-2-Notification]

PREETI SELLARE, Dy. Director (OL)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026

का.आ. 329.—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3575(अ) तारीख 31.07.2025 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 04.08.2025 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से

संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा असम राज्य में सिलचर सीजीडी स्पर लाइन ऑफ गुवाहाटी-शिलांग-सिलचर-पानीसागर प्रकृतिक गैस पाइपलाइन के मध्यम से प्रकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइने बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला : कछार				राज्य : असम		
सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कटीगोरह	भंगेरपार पार्ट-3	भंगेरपार पार्ट-3	205	00	41	03
			183	00	04	58
कटीगोरह	भंगेरपार पार्ट-5	भंगेरपार पार्ट-5	247	00	12	09
कटीगोरह	चंदपुर पार्ट-3	चंदपुर पार्ट-3	29	00	08	25
कटीगोरह	निज़ कटिगोराह पार्ट-2	निज़ कटिगोराह पार्ट-2	203	00	01	20
			204	00	01	21
			205	00	00	42
			218	00	01	36
			216	00	02	95
			227	00	01	96
कटीगोरह	रंघर पार्ट-3	रंघर पार्ट-3	203	00	14	10
सिलचर	हैरबोन्ड पार्ट-2	हैरबोन्ड पार्ट-2	100	00	09	65
			106	00	11	29
			323	00	08	94
सिलचर	दुर्गापुर	दुर्गापुर	04	00	13	81
			168	00	05	87

			190	00	08	67
			235	00	06	15
सिलचर	उजान ग्राम	उजान ग्राम	211	00	01	90
			214	00	00	40
			209	00	04	60
			208	00	11	00
			194	00	04	00
			197	00	05	10
			431	00	03	18
			432	00	07	32
उदरबोन्ड	दुर्गानगर पार्ट-4	दुर्गानगर पार्ट-4	226	00	13	30
			227	00	04	30
			229	00	01	61
			224	00	04	00
उदरबोन्ड	डोयापोर पार्ट- 4	डोयापोर पार्ट- 4	140	00	00	39
			142	00	40	00
			67	00	05	40
			68	00	02	63
			72	00	02	93
			126	00	00	42
			125	00	01	42
			69	00	00	20
सोनई	धनेहरी पार्ट-१	धनेहरी पार्ट-१	13	00	65	77
			17	00	07	32
			18	00	04	34
			19	00	30	92
			40	00	01	00
			41	00	45	77
			42	00	06	12
			44	00	29	45
			48	00	38	58
			228	00	00	72
			398	00	00	10
			399	00	02	87
			401	00	03	14
			406	00	07	54
			408	00	00	86
			407	00	05	13
			464	00	04	90
			462	00	01	13
			463	00	01	57
			466	00	02	78
			455	00	06	65
			454	00	00	75
			453	00	00	05
			458	00	01	12

			468	00	02	23
			469	00	09	94
			472	00	01	33
			473	00	12	39
			474	00	02	47
			475	00	02	16
			478	00	07	90
			479	00	03	51
			485	00	03	38
			487	00	04	60
			489	00	03	34
			490	00	11	80
			572	00	03	52
			580	00	12	26
			581	00	00	96
			584	00	05	62
			585	00	06	62
			586	00	06	70
			597	00	02	18
सोनई	बागपुर पीटी 1	बागपुर पीटी 1	346	00	05	35
			510	00	20	52
			502	00	11	35
			501	00	03	59
			500	00	03	89
			503	00	00	80
			498	00	06	61
			499	00	01	00
			493	00	30	14
			491	00	00	20
			492	00	00	75
			451	00	01	70
			448	00	08	18
			446	00	02	19

			447	00	01	60
			385	00	03	87
			386	00	02	68
			384	00	04	74
			378	00	10	41
			387	00	16	35
			390	00	16	98
			393	00	22	49
			396	00	04	51
			449	00	00	70
			450	00	00	90

[फा. सं. एल - 14014/249/2022 - जी पी - II(ई - 45396)]

रामजी लाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 10th March, 2026

S.O. 329.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.3575(E) dated the 31.07.2025, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 04.08.2025, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Silchar CGD Spur line of Guwahati - Shillong - Silchar - Panisagar Section of North - East Natural Gas Pipeline in the state of Assam by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE

District : Cachar			State: Assam			
Circle	Mauza	Village	Dag No.	Area		
				Hec.	Arc	Sq.Mtr.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Katigorah	Bhangerpar Part-3	Bhangerpar Part-3	205	00	41	03
			183	00	04	58

Katigorah	Bhangerpar Part-5	Bhangerpar Part-5	247	00	12	09
Katigorah	Chandpur Part-3	Chandpur Part-3	29	00	08	25
Katigorah	Niz-Katigorah Part-2	Niz-Katigorah Part-2	203	00	01	20
			204	00	01	21
			205	00	00	42
			218	00	01	36
			216	00	02	95
			227	00	01	96
Katigorah	Ranghar Part-3	Ranghar Part-3	203	00	14	10
Silchar	Heirbond Part-2	Heirbond Part-2	100	00	09	65
			106	00	11	29
			323	00	08	94
Silchar	Durgapur	Durgapur	4	00	13	81
			168	00	05	87
			190	00	08	67
			235	00	06	15
Silchar	Ujangram	Ujangram	211	00	01	90
			214	00	00	40
			209	00	04	60
			208	00	11	00
			194	00	04	00
			197	00	05	10
			431	00	03	18
			432	00	07	32
Udharbond	Durganagar Part-4	Durganagar Part-4	226	00	13	30
			227	00	04	30
			229	00	01	61
			224	00	04	00
Udharbond	Doyapore Part-4	Doyapore Part-4	140	00	00	39
			142	00	40	00
			67	00	05	40
			68	00	02	63
			72	00	02	93
			126	00	00	42
			125	00	01	42
			69	00	00	20
Sonai	Dhanehari Part 1	Dhanehari Part 1	13	00	65	77
			17	00	07	32
			18	00	04	34
			19	00	30	92
			40	00	01	00
			41	00	45	77
			42	00	06	12
			44	00	29	45
			48	00	38	58
			228	00	00	72
			398	00	00	10
			399	00	02	87
			401	00	03	14
			406	00	07	54
			408	00	00	86
			407	00	05	13
			464	00	04	90
			462	00	01	13
			463	00	01	57
			466	00	02	78
			455	00	06	65
			454	00	00	75

			453	00	00	05
			458	00	01	12
			468	00	02	23
			469	00	09	94
			472	00	01	33
			473	00	12	39
			474	00	02	47
			475	00	02	16
			478	00	07	90
			479	00	03	51
			485	00	03	38
			487	00	04	60
			489	00	03	34
			490	00	11	80
			572	00	03	52
			580	00	12	26
			581	00	00	96
			584	00	05	62
			585	00	06	62
			586	00	06	70
			597	00	02	18
Sonai	Bagpur Pt-1	Bagpur Pt-1	346	00	05	35
			510	00	20	52
			502	00	11	35
			501	00	03	59
			500	00	03	89
			503	00	00	80
			498	00	06	61
			499	00	01	00
			493	00	30	14
			491	00	00	20
			492	00	00	75
			451	00	01	70
			448	00	08	18
			446	00	02	19
			447	00	01	60
			385	00	03	87
			386	00	02	68
			384	00	04	74
			378	00	10	41
			387	00	16	35
			390	00	16	98
			393	00	22	49
			396	00	04	51
			449	00	00	70
			450	00	00	90

[F. No. L – 14014/249/2022- G P - II (E - 45396)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026

का.आ. 330.—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. No.3487(E) तारीख 12.08.2024 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 14.08.2024 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा असम राज्य में गुवाहाटी – नुमालीगढ़ प्रकृतिक

गैस पाइपलाइन के मधायम से प्रकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतःअब, भारतसरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइने बिछाने के लिए भूमि मे उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्सइंद्रधनुषगैसग्रिडलिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्सइंद्रधनुषगैसग्रिडलिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला :जोरहाट				राज्य : असम		
सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
जोरहाट पश्चिम	बालिगांव	मालौखाट	2475	00	02	68

[फा. सं. एल - 14014/1/2024 - जी पी - II(ई - 48822)]

रामजी लाल मीना, अवर सचिव

New Delhi, the 10th March, 2026

S.O. 330.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.3487(E) dated 12.08.2024, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 14.08.2024, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Guwahati-Numaligarh Gas Pipeline in the state of Assam by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

District: Jorhat				State: Assam		
Circle	Mouza	Name of Village	Dag No.	Area		
				Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jorhat West	Baligaon	Malow Khat	2475	00	02	68

[F. No. L – 14014/1/2024- G P - II (E - 48822)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026

का.आ. 331.—जबकि भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि असम राज्य में नार्थ – इस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना के गुवाहाटी-नुमालीगढ़ - दीमापुर खंड के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतःअब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने की संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, असम राज्य, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला : गोलाघाट				राज्य : असम		
सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सरूपथार	बारपथार	रेंगमा ग्रांट	259	00	09	39

[फा. सं. एल – 14014/18/2023 - जी पी - II(ई - 47090)]

रामजी लाल मीना, अवर सचिव

New Delhi, the 10th March, 2026

S.O. 331.—Whereas it appears to the Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Guwahati – Numaligarh – Dimapur Section of North - East Natural Gas Pipeline Grid Project in the State of Assam, a pipeline should be laid by M/s Indradhanush Gas Grid Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, M/s Indradhanush Gas Grid Limited, State of Assam.

SCHEDULE

District: Golaghat			State: Assam			
Circle	Mouza	Village	Dag No.	Area		
				Hectare	Are	Square Meter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sarupathar	Barpathar	Rengma Grant	259	00	09	39

[F. No. L – 14014/18/2023- G P - II (E - 47090)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

श्रम और रोजगार मन्त्रालय

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026

का.आ. 332.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रबंधन, संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं 2 मुंबई के पंचाट (6/2020) प्रकाशित करती है।

[सं. एल-12011/04/2020-आई आर(वी-1)]

सलोनी, उप निदेशक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 10th March, 2026

S.O. 332.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. 6/2020) of the *Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No. 2 Mumbai* as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. ICICI Bank Limited and their workmen.

[No. L-12011/04/2020- IR (B-I)]

SALONI, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE JUSTICE RETIRED SHIV SHANKER PRASAD

PRESIDING OFFICER/LINK OFFICER

THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.2, MUMBAI

PRESENT

JUSTICE RETIRED SHIV SHANKER PRASAD

Presiding Officer/Link Officer

REFERENCE NO. CGIT-2/6 of 2020

EMPLOYERS IN RELATION TO THE MANAGEMENT OF

First Party No. 1. M/s. ICICI Bank Limited

The General Manager, Head-HR,

M/s. ICICI Bank Limited,

South Tower,

9th Floor, West Wing,

Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai 400 051.
State: Maharashtra

2. M/s. Proklean Services

M/s. Proklean Services,
10, Aishwarya Towers,
Ground Floor,
Kalina,
Santacruz (E),
Mumbai 400 055.
State: Maharashtra

3. M/s. Rare Hospitality & Services Pvt. Ltd.,

M/s. Rare Hospitality & Services Pvt. Ltd.,
10, Aishwarya Towers,
Ground Floor,
Kalina,
Santacruz (E),
Mumbai 400 055.
State: Maharashtra

AND

THEIR WORKMEN.

Party No. 2 (Bhartiya Kamgar Karmachari Mahasangh)

The Vice President,
Bhartiya Kamgar Karmachari Mahasangh
5, Navalkar Lane, 1st Floor,
Prarthana Samaj,
Girgaon,
Mumbai- 400 004,
Mumbai.

APPEARANCES:

Management	:	No appearance.
Workmen	:	No appearance.

AWARD

(Delivered on 22-01-2026)

1. This Reference has been made by the Central Government in exercise of powers under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, vide Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi, order No. L-12011/04/2020 (IR(B-I) dated 17.02.2020. The terms of reference given in the schedule are as follows:

“Whether the management of ICICI Bank Ltd., and M/s. Proklean Services, Contractor is liable to pay payment of Rs.1560/- per month to their workmen at par with other set of office boys alongwith arrears of last two years? Whether the present dispute is legal and justified? If not, what relief the workers are entitled?”

2. The case is called out today. Both parties are absent. From perusal of record, it is apparent that, the petitioner/workman is not responding and attending the Court since 22.07.2022 long back despite service of notice. No Statement of Claim has been filed by the petitioner/workman till today. The respondent has also not filed his Written Statements till now. Both parties are absent. Both parties are not coming to the Court since long back. It appears that, both parties are not interested to contest the case furthermore. The claim of the petitioner is not proved. So, the case is closed.

Hence, it is ordered.

ORDER

The management of ICICI Bank Ltd., and M/s. Prokean Services, Contractor is not liable to pay payment of Rs.1560/- per month to their workmen at par with other set of office boys alongwith arrears of last two years. The present dispute is not legal and justified. The workers are not entitled to any relief.

Date: 22-01-2026

Justice SHIV SHANKER PRASAD, Presiding Officer/Link Officer

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026

का.आ. 333.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधन के संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (कॉम्प.केस. क्रमांक 01/2022 .रेफ केस क्रमांक 62/2008) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/96/2008-आई आर(सीएम-1)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 10th March, 2026

S.O. 333.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Comp.Case. No. 01/2022 .Refe Case No. 62/2008**) of the **Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of **BCCL**. and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**.

[No. L-20012/96/2008- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1, DHANBAD

Comp. Case No. 01/2022

Arising out of REF Case No. 62/2008

Saroj Kumar Singh

Store Keeper, Bera Colliery

M/s. BCCL, Dhanbad.....Complainants

Vs.

Project Officer,

Bera Colliery, Bastacolla Area

M/s. BCCL, Dhanbad.....Opposite

Parties

Appearances:

For Complainant :- None.

For Opp. Party :- None.

Present: **Shri Sachindra Kumar Pandey**

Presiding Officer

State : Jharkhand

Dated 04/02/2026

ORDER

2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.

3. Case is called out.

4. On call none is present from either side.

5. Perused the record. After perusal of record it appears that concerned workman appeared on 24.01.2022 and filed an application under section 33 of I.D. Act, 1947 and regd. Notice was issued to opposite party and both the parties appeared for certain dates. On 07.01.2026 Shri D.K. Verma, Ld. Advocate for the Opp. Party appeared and submitted that original case Ref No. 62/2008 from which this case arises has been disposed of on 28.09.2022 so case may be closed.

6. In view of the fact that the original case has already been decided against the complainant, this case has no merit and is hereby dismissed.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026

का.आ. 334.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधन के संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 58/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/21/2004-आई आर(सीएम-1)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 10th March, 2026

S.O. 334.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 58/2004**) of the **Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of **BCCL**, and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**

[No. L-20012/21/2004- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD**In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.**Reference Case No. 58/2004****Parties:**

Employers in relation to the management of Govindpur Area-III

Of M/s. BCCL, Dhanbad

AND

Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- Sri Ankit Shrivastava, Dy. Manager (HR)

For the workman :- None.

State : Bihar.

Industry:-Coal

Dated 04/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/21/2004 IR(C-I) dated 08/16.06.2004 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Govindpur Area -III of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Vice President, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“क्या राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ की भा को को लि, गोविंदपुर क्षेत्र - III के प्रबंधतंत्र से माँग कि कर्मकार श्री जागेश्वर सिंह को माइनर लोडर से माइनिंग सिरदार के पद पर पदोन्नती पर वेतन निर्धारण में उन्हें पूर्व वेतन में पे-प्रोटेक्शन दिया जाए, उचित एवं न्यायसंगत है? यदि हाँ तो कर्मकार किस राहत के पात्र हैं तथा किस तारीख से ?”

2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.

3. On receiving order no. L-20012/21/2004 IR(C-I) dated 08/16.06.2004 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 58 of 2004 was registered on 28.06.2004 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

4. After service of notice, both parties appeared previously. It further appears that after 2006 this case was put up on 26.11.2021 and registered notices were issued to both the parties but workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared. Today Sri Ankit Shrivastava, Dy. Manager (HR) is present but workman/union remained absent before the Tribunal. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal since 2021 which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution.

5. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026

का.आ. 335.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 65/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/55/2004-आई आर(सीएम-1)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 10th March, 2026

S.O. 335.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 65/2004) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of CCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026

[No. L-20012/55/2004- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD**

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 65/2004**Parties:**

Employer in relation to the management of Giridih Area
of M/s. CCL, Giridih

AND

Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- None.

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 04/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/55/2004 -IR(C-I) dated 28/06/2004 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Giridih Area of M/s. CCL, Giridih and their workman through Secretary, United Coal Workers Union, Giridih for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“क्या सी सी एल, गिरिदीह क्षेत्र के प्रबंधतंत्र द्वारा कर्मकार श्री मकबूल अली को पीस रेट से टाइम रेट में नियमित किए जाने के समय उनको पूर्व देय वेतन एवं SPRA का प्रोटेक्शन न दिया जाना उचित एवं न्यायसंगत है? यदि नहीं तो कर्मकार किस राहत के पात्र हैं तथा किस तारीख से ?”

2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.

3. On receiving order no. L-20012/55/2004 -IR(C-I) dated 28/06/2004 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 65 of 2004 was registered on 12.07.2004 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

4. After service of notice, both parties appeared previously. It further appears that after 2006 this case was put up after a long gap on 20.12.2021 and registered notices were issued to both the parties but workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal since 2021 which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution.

5. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026

का.आ. 336.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण – सह – श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 60/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/29/2002-आई आर(सीएम-1)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 10th March, 2026

S.O. 336.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 60/2002**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of **BCCL**, and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**

[No. L-20012/29/2002– IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 60/2002

Parties:

Employers in relation to the management of Kusunda Area
of M/s. BCCL, Kusunda, Dhanbad

AND

Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- Sri Chandra Prakash, Manager (HR)

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 04/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/29/2002 -IR(C-I) dated 30/05/2002 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Kusunda Area of M/s BCCL, Dhanbad and their workman through Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union, Hirapur, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of M/s. BCCL in dismissing Sri Bablu Hari of Industry Colliery from the services of the company w.e.f. 1.12.2000 is fair and justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?”

2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.

3. On receiving order no. L-20012/29/2002- IR(C-I) dated 30/05/2002 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 60 of 2002 was registered on 10.06.2002 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

4. After receipt of the reference on 10.06.2002, this case was put up after a long gap on 30.07.2021 and regd. notices were issued to both the parties but neither the workman nor the management appeared before this Tribunal. Today Sri Chandra Prakash, Manager (HR) appeared for the management but workman/union failed to appear.

5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since beginning which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.

6. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026

का.आ. 337.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 42/2015) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/91/2015-आई आर(सीएम-1)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 10th March, 2026

S.O. 337.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 42/2015**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of **BCCL** and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**.

[No. L-20012/91/2015- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 42/2015

Parties:

Employer in relation to the management of Bastacolla Area
Of M/s. BCCL, Jharia, Dhanbad

AND

Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- None.

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 04/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub -section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/91/2015 -IR(CM-I) dated 17/09/2015 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Bastacolla Area of M/s. BCCL, Jharia, Dhanbad and their workman through Central Secretary, Jharkhand Colliery Mazdoor Union, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the Management of Ghanoodih Colliery of M/s BCCL in dismissing Shri Suresh Kumar, Pers. No. 02830552, Ex-Miner Loader from the services of the Company vide order dated 01/03.02.1999 is justified and fair? To what relief the concerned workman is entitled to?”

2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.
3. On receiving order no. L-20012/91/2015 -IR(CM-I) dated 17/09/2015 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 42 of 2015 was registered on 01.10.2015 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.
4. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder. It further appears that after 03.02.2023 workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri Nitish Sahay, Ld. Advocate on behalf of the management appeared on certain dates but after 23.07.2025 he also failed to appear.
5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since 2023 which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.
6. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026

का.आ. 338.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 41/2010) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/55/2010-आई आर(सीएम-1)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 10th March, 2026

S.O. 338.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 41/2010**) of the **Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of **BCCL**, and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**

[No. L-20012/55/2010- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD**

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 41/2010**Parties:**

Employer in relation to the management of E.J. Area
Of M/s. BCCL, Bhowra, Dhanbad

AND

Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- None.

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 04/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/55/2010 -IR(CM-I) dated 27/07/2010 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of E.J. Area of M/s. BCCL, Bhowra, Dhanbad and their workman through Treasurer, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the management for allegedly not providing employment to Ms. Bhakti Kumari, the daughter of deceased workman namely Chhota Dasi Bouri is legal and justified? To what relief the claimant entitled for?”

2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.

3. On receiving order no. L-20012/55/2010 -IR(CM-I) dated 27/07/2010 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 41 of 2010 was registered on 11.08.2010 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

4. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder. It further appears that after 2018 this case was put up after a long gap on 06.10.2025 and registered notices were issued to both the parties but workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared.

5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since November 2017 which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.

6. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026

का.आ. 339.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दामोदर घाटी निगम के प्रबंधन के संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण – सह – श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 25/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/171/2002-आईआर-(सीएम-II)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 10th March, 2026

S.O. 339.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 25/2003**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of **Damodar Valley Corporation** and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**

[No. L-42012/171/2002– IR (CM-II)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1, DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d) & (2A) of I.D. Act. 1947.
Reference Case No. 25/2003

Parties:

Employers in relation to the management of Damodar Valley
 Corporation, Kolkata
 AND

Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
 Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- None.

For the workman :- None.

State : Bihar.

Industry:-Power
 Dated 04/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-42012/171/2002 IR(CM-II) dated 11/02/2003 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Damodar Valley Corporation, Kolkata and their workman through D.V.C. Staff Association, Maithon Dam, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Damodar Valley Corporation in imposing penalty of stoppage of annual increments and recovery of 50% of Rs. 43238.93 in equal monthly instalments against the cost of pilferage of material, on Sri S.K. Das is fair and justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled to?”

2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.

3. On receiving order no. L-42012/171/2002- IR(CM-II) dated 11/02/2003 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 25 of 2003 was registered on 18.03.2003 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

4. After receipt of the reference, Sri A.S. Das, Committee Member of the sponsoring union appeared and filed written statement on 05.04.2004 but after that failed to appear. However management appeared on certain dates. After 24.08.2007 this case was put up on 17.09.2021, but no step was taken from both sides and regd. notices were again issued on 30.05.2025 to both the parties for appearance and on 08.08.2025, Sri Tapas Rai, Dy. Manager (H.R.) appeared on behalf of the management but workman/union failed to appear. Thereafter management also failed to appear before this Tribunal.

5. On perusal of the entire case record it transpires that both the parties have lost their interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.

6. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026

का.आ. 340.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण – सह – श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 19/2011) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/53/2010-आई आर(सीएम-1)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 10th March, 2026

S.O. 340.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 19/2011**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of **BCCL**. and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**

[No. L-20012/53/2010– IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 19/2011

Parties:

Employers in relation to the management of Kusunda Area
of M/s. BCCL, Kusunda, Dhanbad
AND
Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- Sri Chandra Prakash, Manager (HR)

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 04/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/53/2010 -IR(CM-I) dated 29/03/2011 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Kusunda Area of M/s BCCL, Dhanbad and their workman through General Secretary, Coal Mines Engineering Workers Association, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“The dispute of alleged denial of employment to the dependant of Late Shankar Das is not deemed fit for adjudication as the deceased workman was dismissed from services prior to his death and there is no provision under NCWA for providing employment to the dependant of a dismissed workman”

2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.

3. On receiving order no. L-20012/53/2010- IR(CM-I) dated 29/03/2011 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 19 of 2011 was registered on 11.04.2011 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

4. After receipt of the reference on 11.04.2011, this case was put up after a long gap on 27.01.2022 and regd. notices were issued to both the parties but workman/union failed to appear before this Tribunal and notice of the union returned with endorsement “Incomplete Address” However Sri N. Nath, O.S. Legal H.Q. on behalf of the management appeared. Today Sri Chandra Prakash, Manager (HR) appeared for the management but workman/union failed to appear.

5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since begining which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.

6. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026

का.आ. 341.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में **केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय, धनबाद-I** के पंचाट (संदर्भ संख्या 61/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को **09/03/2026** को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/53/2004-आई आर(सीएम-I)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 10th March, 2026

S.O. 341.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 61/2004**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of CCL. and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**.

[No. L-20012/53/2004- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD**In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.**Reference Case No. 61/2004****Parties:**

Employers in relation to the management of Giridih Area
Of M/s. CCL, Giridih
AND
Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- None.

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 04/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub -section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/53/2004 -IR(C-I) dated 28/06/2004 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Giridih Area of M/s. CCL, Giridih and their workman through Secretary, United Coal Workers Union, Giridih for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Giridih Colliery under Giridih Area of M/s C.C.L., PO-Beniadih, Distt-Giridih in not correcting the date of appointment of Sri Tahi Mian, Ex-Mining Sirdar from 10.1.1970 to 1.1.1959 as per record and also not paying the retirement benefits and other legal dues counting his service w.e.f. 1.1.1959 is proper and justified? If not, to what relief is the workman entitled?”

2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.

3. On receiving order no. L-20012/53/2004- IR(C-I) dated 28/06/2004 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 61 of 2004 was registered on 12.07.2004 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant

documents and witnesses in support of their claims.

4. After receipt of the reference on 12.07.2004, this case was put up after a long gap on 25.11.2021 and regd. notices were issued to both the parties but neither the workman nor the management appeared before this Tribunal and the notice of the union returned with endorsement "Insufficient Address".

5. On perusal of the entire case record it transpires that both the parties have lost their interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.

6. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a "No Dispute Award" be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026

का.आ. 342.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में **केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय, धनबाद-I** के पंचाट (संदर्भ संख्या 35/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/559/2001-आई आर(सीएम-1)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 10th March, 2026

S.O. 342.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 35/2002**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of **BCCL** and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**.

[No. L-20012/559/2001- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 35/2002

Parties:

Employer in relation to the management of Amlabad Colliery
Of M/s. BCCL, Amlabad, Dhanbad

AND

Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- None

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 03/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/559/2001-IR(C-I) dated 28/02/2002 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Amlabad Colliery of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through General Secretary, Jharkhand Janta Mazdoor Union, Koylanagar, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the management of Amlabad Colliery’s is justified in dismissing Shri Arjun Bhuiya from service. If not, to what relief is the workman concerned entitled?”

2. On receiving order no. L-20012/559/2001-IR(C-I) dated 28/02/2002 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 35 of 2002 was registered on 21.03.2002 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

3. After receipt of the reference on 21.03.2002, this case was put after a long gap on 31.12.2015 and Sri Pintu Mondal, Representative for the workman appeared and a notice was issued to the management and thereafter both the parties appeared for certain dates and filed their Authority and written statement and after 20.12.2017, Sri U.N. Lall, Advocate for the management failed to appear before this Tribunal. However Sri Pintu Mondal, representative of the union appeared till 23.09.2021 but thereafter did not appear before this Tribunal. On 24.12.2021 Sri Sadhu Sharan Pd., Representative of the union appeared and thereafter he remained present. On 05.08.2025, Sri Pradeep Kumar Singh, Secretary of sponsoring union appeared and filed a petition stating therein that the workman is not interested to contest the case. So case may be closed.

4. As per petition dated 05.08.2025, his prayer is allowed and accordingly this case is hereby dismissed as withdrawn and it is further ordered that “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.आ. 343.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र, संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारो के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं 1 धनबाद के पंचाट (269/2001) प्रकाशित करती है।

[सं. एल - 12011/175/2001- आई आर (बी-II)]

सलोनी, उप निदेशक

New Delhi, the 11th March, 2026

S.O. 343.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. 269/2001) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No. 1,Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Central Bank of India their workmen.

[No. L-12011/175/2001- IR(B-II)]

SALONI, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 269/2001**Parties:**

Employers in relation to the management of Central Bank of India, Patna

AND

Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- None.

For the workman :- None.

State : Bihar.

Industry:-Bank

Dated 22/01/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-12011/175/2001-IR(B-II) dated 10/12/2001 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Central Bank of India, Patna and their workman through Regional Secretary, Bihar State Central Bank Employees Union, Patna for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Central Bank of India, Patna issuing transfer order to the workmen i.e. S/Sh. R.N. Prasad, M.L. Mishra, G.N. Banerjee, N.K. Jha and Rajendra Prasad and post them to their original place of posting as Head Cashier (E) is justified? If not, what relief the workmen are entitled to?”

2. On receiving order no. L-12011/175/2001-IR(B-II) dated 10/12/2001 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 269 of 2001 was registered on 31.12.2001 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

3. After issuance of regd. notice, none appeared on behalf of both the parties. It further transpires from the case record, when the case record was put up after a long gap on 14.01.2021, registered notices were sent to both the parties but even thereafter no step was taken from both sides.

4. On perusal of the entire case record it transpires that both the parties never appeared before this Tribunal for a period of 24 years which shows that both the parties have lost their interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.

5. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.आ. 344.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीबीएमबी के प्रबंधन के संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण – सह – श्रम न्यायालय, चंडीगढ़-॥ के पंचाट (संदर्भ संख्या 33/2019) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल -23012/12/2019 -आई.आर.(सी.एम-II)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 11th March, 2026

S.O. 344.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 33/2019**) of the **Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Chandigarh-II** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of **BBMB** and **their workmen** received by the Central Government on **10/03/2026**

[No. L-23012/12/2019-IR (CM-II)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE

**In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Chandigarh
(Present:- Mr. Kamal Kant, Presiding Officer).**

ID No.33/2019

Registered on:-14.05.2019

Gian Singh S/o Shri Prem Singh, R/o VPO Dehad, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur, Himachal Pradesh.

----- Workman

Versus

1.The Chairman,Bhakra Beas Management Board, Madhya Marg, Sector 19-B, Chandigarh-160019.

2.The Chief Engineer, Bhakra Beas Management Board, BSL Project, Sundernagar-175038.

----Management

Present:- Sh. S C Gupta, AR for workman.

Sh. Sandeep Sharma (Law Officer), AR for respondent no.1 & 2.

Award : 19.12.2025

Central Government vide Notification No.L-23012/12/2019-IR(CM-II) dated 14.05.2019, under sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter called the Act), has referred the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal:-

“Whether the action of management of BBMB in not accepting the demand of Shri Gian Singh S/o Shri Prem Singh for deeming/considering him in continuous service upto age of superannuation and resultantly entitled for consequential benefits is legal, just and valid? If not, to what relief the workman concerned is entitled to and from which date?”

1.The case is fixed for filing affidavit in evidence on behalf of workman. However today, AR for workman made a statement that the workman has expired and none of the legal heirs is coming forward to contest the case. The case may be dispose of accordingly. The statement is recorded separately.

2.Thus, in view of the statement of AR for workman, this Tribunal is left with no choice, except to pass a 'No Claim Award'. Accordingly, 'No Claim Award' is passed in the present reference.

3.Let copy of this award be sent to the Appropriate Government as required under Section 17 of the Act for publication.

KAMAL KANT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.आ. 345.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टिस्को के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 215/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/319/2001-आईआर-(सीएम-I)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 11th March, 2026

S.O. 345.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 215/2001) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of **Tisco.** and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**

[No. L-20012/319/2001- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD**In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.**Reference Case No. 215/2001****Parties:**Employer in relation to the management of Digwadih Colliery
of M/s. TISCO, Dhanbad

AND

Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- None.

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 03/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/319/2001-IR(C-I) dated 24/09/2001 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Digwadih Colliery of M/s. TISCO, Dhanbad and their workman through Joint Secretary, Colliery Karamchari Sangh, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of M/s TISCO, Digwadih Coll. In dismissing Sri Harish Chand from service is justified? If not, to what relief is the workman entitled?”

2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.

3. On receiving order no. L-20012/319/2001-IR(C-I) dated 24/09/2001 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 215 of 2001 was registered on 01.11.2001 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

4. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder. It further appears that after 2006 this case was put up on 17.09.2021 and registered notices were issued to both the parties but workman/union failed to appear before this Tribunal. Thereafter on 04.07.2022 regd. notice was again issued to workman/union but same was returned with endorsement “Insufficient Address”. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate for the management appeared. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal since the year 2021 which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution.

5. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.आ. 346.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधन के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय,

धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 06/2011) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/31/2010-आईआर-(सीएम-I)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 11th March, 2026

S.O. 346.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 06/2011**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of **BCCL** and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**

[No. L-20012/31/2010- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 06/2011

Parties:

Employers in relation to the management of Western Jharia Area of
M/s. BCCL, Moonidih Dhanbad
AND
Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- Kumari Versha, APM

For the workman :- Sri S.S. De, Secretary

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 03/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/31/2010 -IR(CM-I) dated 23/02/2011 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of W.J. Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Secretary, Koyla Ispat Mazdoor Panchayat, Jharia, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Moonidih Project of M/s BCCL in not providing Cat-VI as Fan Operator to Sri Rajak Mia is fair and justified? to what relief the concerned workman is entitled?”

2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.

3. On receiving order no. L-20012/31/2010- IR(CM-I) dated 23/02/2011 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 06 of 2011 was registered on 08.03.2011 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

4. After receipt of the reference this case was put up after a long gap on 27.01.2022 and regd. notices were issued to both the parties but no step was taken from both sides. Thereafter on 20.06.2025, Sri N. Nath, O.S. Legal H.Q. for the management appeared but workman/union failed to appear and regd. notice was again issued to workman/union for appearance and the same was returned with endorsement “Addressee Left”. Though on 03.02.2026, Smt. Varsha, A.P.M., for the management appeared and filed a notice of retirement of concerned workman and submitted that concerned workman is retired on 31.01.2017. Sri S.S. De, Secretary for the union also appeared and prayed to close the case

5. On perusal of the entire case record it transpires that the workman has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.
6. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.आ. 347.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में **केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय, धनबाद-I** के पंचाट (संदर्भ संख्या 25/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/426/2000-आईआर-(सीएम-I)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 11th March, 2026

S.O. 347.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 25/2001**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of **BCCL** and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**

[No. L-20012/426/2000- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 25/2001

Parties:

Employer in relation to the management of Sijua Area
of M/s. BCCL, Sijua, Dhanbad
AND
Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- Sri Jagdish Karmkar, A.P.M.

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 03/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/426/2000 (C-I) dated 25/01/2001 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Sijua Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Organizing Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the demand of the RCMS from the management of M/s BCCL for providing employment to the dependent of Late Somar Chouhan of 9 pit of Loyabad Colliery under Sijua Area No. 5 is justified? If so, to what relief is the said dependent of deceased employee entitled ?”

2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.

3. On receiving order no. L-20012/426/2000 (C-I) dated 25/01/2001 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 25 of 2001 was registered on 01.03.2001 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

4. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder. It further appears that after 2006 this case was put up after a long gap on 23.12.2019 and registered notices were issued to both the parties and both the parties appeared on certain dates and this case is pending for adducing evidence by the workman. Thereafter on 13.11.2025 Sri N.G. Arun, Representative for the workman appeared and prayed time for evidence as last chance but thereafter failed to appear. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal as last chance was given which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution.

5. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.आ. 348.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में **केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय, धनबाद-I** के पंचाट (संदर्भ संख्या 31/2019) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को **09/03/2026** को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/61/2019-आईआर-(सीएम-I)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 11th March, 2026

S.O. 348.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 31/2019) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of **CCL** and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**

[No. L-20012/61/2019- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 31/2019**Parties:**

Employer in relation to the management of Rajrappa Area

Of M/s. CCL, Rajrappa, Ramgarh.

AND

Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- Sri D.K. Verma, Ld. Advocate.

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 03/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/61/2019-IR(CM-I) dated 11/11/2019 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Rajrappa Area of M/s. CCL, Rajrappa, Ramgarh and their workman through Joint Secretary, Jharkhand Koyla Mazdoor Union for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether workmen Bhim Mahto and twenty (20) other drill operators were illegally not given promotion in next higher grade as per II.32 of NCWA VII of Rajrappa Area of M/s BCCL? If yes, then what remedies they are entitled to?”

2. On receiving order no. L-20012/61/2019-IR(CM-I) dated 11/11/2019 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 31 of 2019 was registered on 19.11.2019 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

3. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder. It further appears that after 22.01.2021 workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared. Thereafter on 12.06.2025 second regd. notice was issued to workman/union but he again failed to appear before this Tribunal and the same was returned with endorsement “Refused”. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal since the year 2021 and lastly he refused to receive the notice which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution.

4. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.आ. 349.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में **केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय, धनबाद-I** के पंचाट (संदर्भ संख्या 16/2019) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को **09/03/2026** को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/426/2000-आईआर-(सीएम-I)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 11th March, 2026

S.O. 349.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 16/2019**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of CCL. and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**.

[No. L-20012/426/2000- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 16/2019

Parties:

Employer in relation to the management of Gidi 'A' Colliery
of M/s CCL, Gidi, Hazaribagh
AND
Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- None.

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal
Dated 03/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/87/2013-IR(CM-I) dated 19/02/2019 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Gidi 'A' Colliery of M/s. CCL, Hazaribagh and their workman through Secetary, BCKU, Gidi, Hazaribagh for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Gidi 'A' Colliery of M/s CCL in denying regularization to S/Shri Munshi Mahto and 11 others (List enclosed) is legal, proper and justified?

ii) If not, what benefits they are entitled to and from which date?

iii) And, what other directions are required in this regards.”

LIST OF WORKERS

Sl. No.	Name	Father's Name
1.	Shri Munshi Mahto	Late Lalku Mahto
2.	Shri Raju Pandey	Shri Madan Pandey
3.	Shri Ketar Mahto	Late Ganga Ram Mahto
4.	Shri Basudeo Mahto	Late Chamu Mahto
5.	Shri Chola Ram	Late Laldhari Ram
6.	Shri Saiynath	Late Puran Mahto
7.	Shri Mithlesh	Shri Munshi Mahto
8.	Shri Subhash	Late Bhawani Prajapati
9.	Shri Sanjay Saw	Shri Raghu Saw
10.	Shri Rambilash	Late Gauri Mahto
11.	Shri Gauri Mahto	Late Manki Mahto
12.	Shri Kedar	Shri Sitku Mahto

2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.

3. On receiving order no. L-20012/87/2013-IR(CM-I) dated 19/02/2019 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 16 of 2019 was registered on 19.03.2019 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

3. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder. It further appears that after 04.03.2020 workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate for the management appeared. Thereafter on 20.06.2025 2nd regd. notice was issued to union but he again failed to appear. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal since the year 2021 which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution.

4. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.आ. 350.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में **केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय, धनबाद-I** के पंचाट (संदर्भ संख्या 65/2014) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/45/2014-आईआर-(सीएम-I)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 11th March, 2026

S.O. 350.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 65/2014**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of **BCCL** and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**

[No. L-20012/45/2014— IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD**

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 65/2014**Parties:**

Employer in relation to the management of Bastacolla Area
of M/s. BCCL, Jharia, Dhanbad

AND

Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- Sri Rishi Raj Meena, Asst. Manager Legal

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 03/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/45/2014-IR(CM-I) dated 04/06/2014 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Bastacolla Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Incharge, Jharkhand Colliery Mazdoor Union, Jharia, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Bastacolla Colliery of M/s BCCL in not regularizing Sri Ashok Kumar to the post of Cap Lamp Issue Clerk is fair and justified? To what relief the concerned workman is entitled to?”

2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.

3. On receiving order no. L-20012/45/2014-IR(CM-I) dated 04/06/2014 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 65 of 2014 was registered on 17.06.2014 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

4. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder. It further appears that after 2017 this case was put up on 01.05.2019 and registered notices were issued to both the parties and both the parties appeared on certain dates. After 06.03.2020, workman/union failed to appear before this Tribunal. Thereafter on 31.07.2025 regd. notice was again issued to workman/union and the same was returned with endorsement “Unclaimed”. However Sri Ganesh Prasad, Ld. Advocate on behalf of the management appeared. Today Sri Rishi Raj Meena, Asst. Manager Legal for the management is present. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal since the year 2020 which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution.

5. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.आ. 351.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधन के संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 51/2015) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/114/2015-आईआर-(सीएम-1)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 11th March, 2026

S.O. 351.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 51/2015) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**

[No. L-20012/114/2015- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1, DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d) & (2A) of I.D. Act. 1947.

Reference Case No. 51/2015

Parties:

Employer in relation to the management of Sijua Area
of M/s. BCCL, Sijua, Dhanbad

AND

Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- Sri Jagdish Karmkar, A.P.M.
For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal
Dated 03/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/114/2015 (IR(CM-I)) dated 09/10/2015 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Sijua Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Secretary, Rashtriya Mazdoor Union, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Sijua Area of M/s BCCL in dismissing Sri Mangru Manjhi, M/Loader vide letter dated 6.10.2003 is fair and justified? To what relief the concerned workman is entitle to?”

2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.

3. On receiving order no. L-20012/114/2015-IR(CM-I) dated 09/10/2015 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 51 of 2015 was registered on 02.11.2015 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

4. After receipt of the reference Sri Sunil Kr. Sinha, Secretary for the union appeared and filed written statement and regd. notice was issued to management and both parties appeared for certain dates. Thereafter on 18.01.2018 workman failed to appear and on 06.10.2025 this case put up after a long gap and regd. notices were issued to both the parties and notice of the workman/union returned with endorsement “Addressee not trace”. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate for the management appeared. Today Sri Jagdish Karmkar, APM for the management is present. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal since the year 2018 which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution.

5. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.आ. 352.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधन के संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 38/2015) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/73/2015-आईआर-(सीएम-I)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 11th March, 2026

S.O. 352.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 38/2015) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026

[No. L-20012/73/2015- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1, DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d) & (2A) of I.D. Act, 1947.
Reference Case No. 38/2015

Parties:

Employer in relation to the management of Govindpur Area No.III
of M/s. BCCL, Dhanbad

AND

Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- Sri Amit Kumar, Area Manager, H.R.

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 03/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/73/2015-IR(CM-I) dated 26/08/2015 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Govindpur Area No.III of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Central Secretary, Jharkhand Colliery Mazdoor Union, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Jogidih Colliery under Katras Area of M/s BCCL in dismissing Sri Pando Bouri from the services w.e.f. 2/3.3.2006 is fair and justified? To what relief the concerned workman is entitled to?”

2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.

3. On receiving order no. L-20012/73/2015-IR(CM-I) dated 26/08/2015 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 38 of 2015 was registered on 07.09.2015 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

4. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently documents. It further appears that after 19.03.2021 workman/union failed to appear before this Tribunal till 12.05.2022, thereafter Sri Balmiki Pd., Advocate for the workman appeared on 23.06.2022 after that he again failed to appear and regd. notice was again issued on 14.10.2025 but he failed to appear. However management appeared on certain dates. Today, Sri Amit Kumar, Area Manager, H.R. for the management is present. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal since the year 2022 which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution.

5. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.आ. 353.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेल.चासनल्ला कोलियरी के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 79/2014) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/73/2014-आईआर-(सीएम-1)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 11th March, 2026

S.O. 353.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 79/2014**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of **Sail.Chasnalla Colliery** and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**.

[No. L-20012/73/2014– IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 79/2014

Parties:

Employers in relation to the management of Chasnalla Colliery
of M/S SAIL, Chasnalla, Dhanbad
AND
Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- None.

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 03/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/73/2014 -IR(CM-I) dated 14/08/2014 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Chasnalla Colliery of M/S SAIL, Dhanbad and their workman through Joint Secretary, Bahujan Mazdoor Union, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the Management of Chasnalla Colliery of M/s SAIL in dismissing Sri Birendra Nath Bauri Ex-Mazdoor, Pers. No. 92614 from the services of the Company vide office order dated 21/23.08.1999 is fair and justified? To what relief the concerned workman is entitled?”

2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.

3. On receiving order no. L-20012/73/2014- IR(CM-I) dated 14/08/2014 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 79 of 2014 was registered on 26.08.2014 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

4. After receipt of the reference this case was put up on 17.01.2022 and regd. notices were issued to both the parties but no step was taken from both sides. Thereafter on 04.07.2025 regd. notices were again issued to both the parties and both parties appeared. On 07.01.2026, Sri R.R. Ram, Representative for the workman appeared and submitted that workman is not interested to contest the case so case may be closed.

5. On perusal of the entire case record it transpires that the workman has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.

6. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2026

का.आ. 354.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 17/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/205/2002-आईआर-(सीएम-I)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 12th March, 2026

S.O. 354.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 17/2003**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**.

[No. L-20012/205/2002- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1, DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d) & (2A) of I.D. Act. 1947.

Reference Case No. 17/2003

Parties:

Employer in relation to the management of Block-II Area of
M/s. BCCL, Dhanbad
AND
Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- None.

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 03/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/205/2002-IR(C-I) dated 24/01/2003 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Block-II Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Regional Secretary, Dhanbad Colliery Karamchari Sangh, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“क्या भा. को. को. लि., प्रबंधन द्वारा कर्मकार श्री परमात्मा सिंह उत्पादन-सह-सुरक्षा-सहायक ग्रेड-“बी” बेनीडीह ओ. सी. पी. को कार्यालय आदेश संख्या-मु.म.प्र./ब्लॉक-2/का.वि./464/91 दिनांक 22.7.1991 के अनुसार वर्ष 1991 से उत्पादन-सह-सुरक्षा-सहायक ग्रेड-“बी” के पद पर पदोन्नत न मानना तथा उसे पदोन्नत वेतनमान का लाभ वर्ष 1991 से न प्रदान करना न्यायसंगत, उचित एवं सही है ? यदि नहीं तो कर्मकार किन लाभों के हकदार हैं तथा किस तारीख से?”

2. On receiving order no. L-20012/205/2002-IR(C-I) dated 24/01/2003 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 17 of 2003 was registered on 05.02.2003 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

3. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder. It further appears that after 2006 this case was put up after a long gap on 17.08.2021 and registered notices were issued to both the parties but both the parties failed to appear before this Tribunal and the notice of the union returned with endorsement “अधूरा पता के चलते वापस”. Though on 13.06.2025 Sri N. Nath, O.S. Legal H.Q. appeared for the management and thereafter failed to appear before the Tribunal. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal since the year 2021 which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution.

4. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2026

का.आ. 355.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 188/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/319/2000-आईआर-(सीएम-I)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 12th March, 2026

S.O. 355.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 188/2001**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of CCL. and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**

[No. L-20012/319/2000- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 188/2001

Parties:

Employers in relation to the management of Giridih Area
Of M/s. CCL, Giridih.
AND
Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- None.

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 05/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/319/2000-IR(C-I) dated 29/08/2001 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Giridih Area of M/s. CCL, Giridih and their workman through Regional Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Beniyadih, Giridih for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“क्या राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ की सी. सी. एल. गिरिदीह कोलियरी के प्रबंधतंत्र से माँग कि श्री एच. एल. तिवारी को दी गई पदावनती कि सजा वापस ली जाए उचित एवं न्यायसंगत है ? यदि हाँ तो इस संबंध में क्या आदेश आवश्यक हैं ?”

2. On receiving order no. L-20012/319/2000-IR(C-I) dated 29/08/2001 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 188 of 2001 was registered on 21.09.2001 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

3. After receipt of the reference on 21.09.2001, this case record was put up after a long gap on 17.09.2021 and registered notices were sent to both the parties and Sri Rajwardhan Kumar Dy. Manager (P) appeared on 20.12.2021 and filed his letter of authority on behalf of management but thereafter neither the workman nor the management appeared before this Tribunal.

4. On perusal of the entire case record it transpires that both the parties never appeared before this Tribunal since 31.01.2022 which shows that the both the parties have lost their interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.

5. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2026

का.आ. 356.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 92/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/111/2004-आईआर-(सीएम-1)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 12th March, 2026

S.O. 356.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 92/2004) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026

[No. L-20012/111/2004- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1, DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d) & (2A) of I.D. Act. 1947.

Reference Case No. 92/2004

Parties:

Employers in relation to the management of Western Jharia Area

Of M/s. BCCL, Moonidih, Dhanbad

AND

Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- None.

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 05/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/111/2004-IR(C-I) dated 02/09/2004 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Western Jharia Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Executive Chairman, Bihar Janta Khan Mazdoor Sangh, Moonidih, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Western Jharia Area of M/s BCCL, PO-Moonidih, Distt-Dhanbad in not giving Shri Keshar Manjhi pay protection while placing/regularizing him from Tyndel, Category-IV to the post of Driver, Cat-V is proper and justified? If not, to what relief is the workman entitled?”

2. On receiving order no. L-20012/111/2004-IR(C-I) dated 02/09/2004 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 92 of 2004 was registered on 14.09.2004 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

3. After receipt of the reference on 14.09.2004, this case record was put up after a long gap on 20.12.2021 and registered notices were sent to both the parties but neither the workman nor the management appeared before this Tribunal.

4. On perusal of the entire case record it transpires that both the parties never appeared before this Tribunal since beginning which shows that both the parties have lost their interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.

5. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2026

का.आ. 357.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधन के संबंध नियोजको और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में **केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय, धनबाद-I** के पंचाट (संदर्भ संख्या 81/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को **09/03/2026** को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/48/2002-आईआर-(सीएम-I)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 12th March, 2026

S.O. 357.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 81/2006**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of CCL and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**.

[No. L-20012/48/2002- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 81/2006

Parties:

Employers in relation to the management of Hendegir Colliery
 Of M/s. CCL, Ranchi
 AND
 Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
 Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- Sri D.K. Verma, Ld. Advocate
 For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal
 Dated 05/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/48/2002-IR(CM-I) dated 30/08/2006 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Hendegir Colliery of M/s. CCL, Ranchi and their workman through President, N.C.O.E.A., Hendegir, Ranchi for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the demand of the NCOEA from the management of CCL, Hendegir Colliery to give employment to Sri. Jaysree Ganjhu the dependent of the deceased workman Smt. Late Bigni Reja as per the provision of NCWA-V is justified? If so, to what relief is the said dependent entitled ?”

2. On receiving order no. L-20012/48/2002-IR(CM-I) dated 30/08/2006 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 81 of 2006 was registered on 15.09.2006 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

3. After receipt of the reference on 15.09.2006, this case record was put up after a long gap on 20.12.2021 and registered notices were sent to both the parties and both the parties appeared before this Tribunal on 14.03.2022 but thereafter workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared.

4. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal after 14.03.2022 which shows that the workman/union has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.

5. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2026

का.आ. 358.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण – सह – श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 21/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/475/2001-आईआर-(सीएम-I)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 12th March, 2026

S.O. 358.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 21/2002**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**

[No. L-20012/475/2001– IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 21/2002

Parties:

Employer in relation to the management of P.B. Area

Of M/s. BCCL, Kusunda, Dhanbad

AND

Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- Sri D.K. Verma, Ld. Advocate.

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 05/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/475/2001-IR(C-I) dated 20/02/2002 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of P.B. Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Vice President, Mines Mazdoor Union, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Gopalichak Colliery of M/s BCCL in dismissing Sri Ghasi Ram Bouri from the services of the company w.e.f. 17.6.2000 is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?”

2. On receiving order no. L-20012/475/2001-IR(C-I) dated 20/02/2002 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 21 of 2002 was registered on 21.03.2002 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

3. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently

rejoinder. It further appears that after 2006 this case was put up after a long gap on 28.07.2021 and registered notices were issued to both the parties and Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared but workman/union failed to appear before this Tribunal and the notice of the workman/union returned with endorsement "Incomplete Address". However, Sri D.K. Verma, Ld. Advocate for the management appeared. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal since the year 2021 which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution.

4. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a "No Dispute Award" be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2026

का.आ. 359.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधन के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में **केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय, धनबाद-I** के पंचाट (संदर्भ संख्या 62/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को **09/03/2026** को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/59/2004-आईआर-(सीएम-I)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 12th March, 2026

S.O. 359.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 62/2004**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of CCL. and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**

[No. L-20012/59/2004- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1, DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d) & (2A) of I.D. Act. 1947.

Reference Case No. 62/2004

Parties:

Employer in relation to the management of Churi Colliery under
N.K. Area of M/s. C.C.L., Ray, Ranchi
AND
Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- Sri D.K. Verma, Ld. Advocate.

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal
Dated 05/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/59/2004-IR(C-I) dated 28/06/2004 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Churi Colliery under N.K. Area of M/s. CCL, Ranchi and their workman through Vice President, Janta Mazdoor Sangh, Ray, Ranchi for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Churi Colliery under N K Area of M/s C.C.L., PO-Ray, Distt-Ranchi in not providing employment to Sri Ram Dular Mahato on compassionate grounds as dependent son of Late Mahadeo Mahato, Security Guard under the provisions of N.C.W.A. is proper and justified? If not, to what relief is the said dependent of the deceased workman entitled ?”

2. On receiving order no. L-20012/59/2004-IR(C-I) dated 28/06/2004 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 62 of 2004 was registered on 12.07.2004 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

3. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder. It further appears that after 2007 this case was put up after a long gap on 25.11.2021 and registered notices were issued to both the parties and Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared but workman/union failed to appear before this Tribunal. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal since the year 2021 which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution.

4. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2026

का.आ. 360.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में **केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय, धनबाद-I** के पंचाट (संदर्भ संख्या 37/2011) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को **09/03/2026** को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/101/2010-आईआर-(सीएम-I)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 12th March, 2026

S.O. 360.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 37/2011**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of **BCCL** and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**

[No. L-20012/101/2010- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 37/2011

Parties:

Employer in relation to the management of Sijua Area
of M/s. BCCL, Sijua, Dhanbad
AND
Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- None.

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 05/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/101/2010 -IR(CM-I) dated 07/07/2011 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Sijua Area of M/s BCCL, Sijua, Dhanbad and their workman through Vice President, Janta Mazdoor Sangh, Jharia, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Sendra Bansjora Colliery of M/s BCCL in not providing employment to Smt. Hasina Khatoon, dependant wife of late Allauddin Mia under the provision of NCWA is fair and justified? To what relief the dependent wife of late Allauddin Mia is entitled to?”

2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.

3. On receiving order no. L-20012/101/2010 -IR(CM-I) dated 07/07/2011 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 37 of 2011 was registered on 22.07.2011 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

4. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder. It further appears that Sri K.N. Singh, Representative for the workman appeared on 24.12.2025 and submitted that workman is not interested to contest the case so case may be closed.

5. On perusal of the entire case record it transpires that the workman has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.

6. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2026

का.आ. 361.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधन के संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण – सह – श्रम न्यायालय, धनबाद-1 के पंचाट (संदर्भ संख्या 109/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/101/2002-आईआर-(सीएम-1)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 12th March, 2026

S.O. 361.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 109/2002**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of CCL. and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**

[No. L-20012/101/2002— IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 109/2002

Parties:

Employer in relation to the management of Topa Colliery
Of M/s. CCL, Hazaribagh
AND
Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- Sri D.K. Verma, Ld. Advocate.

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 03/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/101/2002-IR(C-I) dated 07/10/2002 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Topa Colliery of M/s. CCL, Hazaribagh and their workman through Vice President, UCWU, Topa, Hazaribagh for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“क्या यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन की सी. सी. एल. टॉप कोलियरी के प्रबंधन से माँग कि कर्मकार सोना गंजु के आश्रित पुत्र श्री परमेश्वर गंजु को एन सी डब्ल्यू ए के प्रावधानानुसार अनुकंपा आधार पर नियुक्ति का लाभ दिया जाए उचित एवं न्याय संगत है? यदि हाँ तो कर्मकार किस राहत के पात्र हैं?”

2. On receiving order no. L-20012/101/2002-IR(C-I) dated 07/10/2002 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 109 of 2002 was registered on 18.11.2002 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

3. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder but thereafter workman did not appear after 07.02.2003. However management appeared on certain dates. It further appears that after 2006 this case was put up after a long gap on 05.08.2021 and registered notices were issued to both the parties but workman/union again failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal after 07.02.2003 which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution.

4. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2026

का.आ. 362.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में **केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय, धनबाद-I** के पंचाट (संदर्भ संख्या 27/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को **09/03/2026** को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/511/2001-आईआर-(सीएम-I)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 12th March, 2026

S.O. 362.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 27/2002**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**

[No. L-20012/511/2001- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD**In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.**Reference Case No. 27/2002****Parties:**

Employer in relation to the management of Block-II Area
Of M/s. BCCL, Nawagarh, Dhanbad
AND
Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- Sri D.K. Verma, Ld. Advocate.

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 03/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub -section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/511/2001-IR(C-I) dated 20/02/2002 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Block-II Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Organizing Secretary, Dhanbad Colliery Karamchari Sangh, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ब्लॉक-II क्षेत्र के प्रबंधतंत्र द्वारा, श्री मिथलेश प्रसाद सिंह, केयर टेकर को 5.7.1990 से टेक्निकल ग्रेड “बी” न दिया जाना उचित तथा उक्त ग्रेड का वेतन न दिया जाना उचित एवं न्याय संगत है? यदि नहीं तो कर्मकार किस राहत के पात्र हैं?”

2. On receiving order no. L-20012/511/2001-IR(C-I) dated 20/02/2002 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 27 of 2002 was registered on 21.03.2002 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

3. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder. It further appears that after 2006 this case was put up after a long gap on 30.07.2021 and registered notices were issued to both the parties but workman/union did not appear before the Tribunal. However, Sri D.K. Verma, Ld. Advocate for the management appeared. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal since the year 2021 which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution.

4. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2026

का.आ. 363.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधन के संबंध नियोजको और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में **केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय, धनबाद-I** के पंचाट (संदर्भ संख्या 22/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को **09/03/2026** को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/515/2001-आईआर-(सीएम-I)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 12th March, 2026

S.O. 363.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 22/2002**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of **CCL**. and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**.

[No. L-20012/515/2001- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 22/2002

Parties:

Employer in relation to the management of Karo Spl. Project
of M/s. CCL Ltd., Bokaro
AND
Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- Sri D.K. Verma, Ld. Advocate.

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 03/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/515/2001-IR(C-I) dated 20/02/2002 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Karo Spl. Project of M/s. CCL, Bokaro and their workman through Zonal Secretary, N.C.O.E.A, Bokaro Thermal, Bokaro for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Karo Spl. Project of M/s CCL, to dismiss the services of Shri Rasik Manjhi, workman is fair, justified and legal? If not, to what relief is the workman concerned entitled?”

2. On receiving order no. L-20012/515/2001-IR(C-I) dated 20/02/2002 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 22 of 2002 was registered on 21.03.2002 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

3. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder. It further appears that after 2006 this case was put up after a long gap on 30.07.2021 and registered notices were issued to both the parties and on 20.09.2021, Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared but workman/union failed to appear and a regd. notice was again sent to the workman/union but he did not appear before the Tribunal. However, Sri D.K. Verma, Ld. Advocate for the management appeared. It transpires from the case record that workman/union failed to appear before the Tribunal since the year 2021 which shows that workman/union has lost his interest in this case and therefore, this Tribunal is of the opinion that the case deserves to be dismissed due to non prosecution.

4. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026

का.आ. 364.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधन के संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 79/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/582/2001-आईआर-(सीएम-1)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 13th March, 2026

S.O. 364.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 79/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of CCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026.

[No. L-20012/582/2001- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1, DHANBAD**

In the matter of reference U/S 10 (1) (d) & (2A) of I.D. Act. 1947.

Reference Case No. 79/2006**Parties:**

Employers in relation to the management of Hendegir Colliery
of M/s. CCL, Hendegir, Ranchi

AND

Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- Sri D.K. Verma, Ld. Advocate.

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 06/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/582/2001-IR(CM-I) dated 30/08/2006 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Hendegir Colliery of M/s BCCL, Ranchi and their workman through President, N.C.O.E.A., Hendegir, Ranchi for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the demand of the NCOEA from the management of CCL, Hendegir Colliery to give employment to Smt. Jharmani Devi the dependent of the deceased workman Shri Late Jharia Ganju as per the provision of NCWA-V is justified? If so, to what relief is the said dependent entitled?”

2. On receiving order no. L-20012/582/2001-IR(CM-I) dated 30/08/2006 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 79 of 2006 was registered on 15.09.2006 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

3. After receipt of the reference on 15.09.2006, this case record was put up after a long gap on 20.12.2021 and registered notices were sent to both the parties and both parties appeared on 14.03.2022 but thereafter workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared.

4. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since April, 2022 which shows that the workman/union has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.

5. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026

का.आ. 365.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधन के संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 78/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/583/2001-आईआर-(सीएम-1)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 13th March, 2026

S.O. 365.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 78/2006**) of the **Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of CCL. and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**

[No. L-20012/583/2001- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD**In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.**Reference Case No. 78/2006****Parties:**

Employers in relation to the management of Hendegir Colliery
of M/s. CCL, Hendegir, Ranchi

AND

Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- Sri D.K. Verma, Ld. Advocate.

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 06/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/583/2001-IR(CM-I) dated 30/08/2006 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Hendegir Colliery of M/s BCCL, Ranchi and their workman through President, N.C.O.E.A., Hendegir, Ranchi for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the demand of the NCOEA from the management of CCL, Hendegir Colliery to give employment to Smt. Shanti Devi the dependent of the deceased workman Shri Late Jhagta Ganjhu as per the provision of NCWA-V is justified? If so, to what relief is the said dependent entitled?”

2. On receiving order no. L-20012/583/2001-IR(CM-I) dated 30/08/2006 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 78 of 2006 was registered on 15.09.2006 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

3. After receipt of the reference on 15.09.2006, this case record was put up after a long gap on 20.12.2021 and registered notices were sent to both the parties and both parties appeared on 14.03.2022 but thereafter workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared.

4. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since April, 2022 which shows that the workman/union has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.

5. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026

का.आ. 366.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में **केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय, धनबाद-I** के पंचाट (संदर्भ संख्या 28/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को **09/03/2026** को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/235/2002-आईआर-(सीएम-I)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 13th March, 2026

S.O. 366.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 28/2003**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of **BCCL** and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**.

[No. L-20012/235/2002- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 28/2003

Parties:

Employers in relation to the management of Kusunda Area
of M/s. BCCL, Kusunda, Dhanbad
AND
Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- None.
For the workman :- Sri Pradeep Kr. Singh, Secretary

State : Jharkhand.

Industry:-Coal
Dated 06/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/235/2002-IR(C-I) dated 10/03/2003 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Kusunda Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through General Secretary, Jharkhand Janta Mazdoor Union, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Godhur Colliery of M/s BCCL in dismissing Sri Badri Bhuia from the services of the company w.e.f. 15.6.2001 is fair and justified? If not to what relief is the concerned workman entitled?”

2. On receiving order no. L-20012/235/2002-IR(C-I) dated 10/03/2003 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 28 of 2003 was registered on 28.04.2003 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.
3. After receipt of the reference on 28.04.2003, this case record was put up after a long gap on 17.09.2021 and registered notices were sent to both the parties and on 07.02.2022 Sri Sadhu Sharan Pd., Representative on behalf of the workman appeared but management failed to appear thereafter workman also failed to appear before this Tribunal. Later on, on 22.08.2025 and 24.10.2025 Sri Pradeep Kumar Singh, Secretary of the union appeared and submitted that concerned workman is not interested to contest this case so case may be closed.
4. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.
5. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026

का.आ. 367.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण – सह – श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 80/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/581/2001-आईआर-(सीएम-1)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 13th March, 2026

S.O. 367.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 80/2006**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of CCL. and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**.

[No. L-20012/581/2001– IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 80/2006

Parties:

Employers in relation to the management of Hendegir Colliery

of M/s. CCL, Hendegir, Ranchi

AND

Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- Sri D.K. Verma, Ld. Advocate.

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 06/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/581/2001-IR(CM-I) dated 30/08/2006 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Hendegir Colliery of M/s BCCL, Ranchi and their workman through President, N.C.O.E.A., Hendegir, Ranchi for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the demand of the NCOEA from the management of CCL, Hendegir Colliery to give employment to Shri Sukhram Manjhi the dependent of the deceased workman Shri Late Dilka Manjhi as per the provision of NCWA-V is justified? If so, to what relief is the said dependent entitled?”

2. On receiving order no. L-20012/581/2001-IR(CM-I) dated 30/08/2006 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 80 of 2006 was registered on 15.09.2006 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

3. After receipt of the reference on 15.09.2006, this case record was put up after a long gap on 20.12.2021 and registered notices were sent to both the parties and both parties appeared on 14.03.2022 but thereafter workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared.

4. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since April, 2022 which shows that the workman/union has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.

5. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026

का.आ. 368.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में **केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय, धनबाद-I** के पंचाट (संदर्भ संख्या 36/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/275/2003-आईआर-(सीएम-I)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 13th March, 2026

S.O. 368.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 36/2004**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**.

[No. L-20012/275/2003- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 36/2004

Parties:

Employer in relation to the management of Bastacolla Area
of M/s. BCCL, Jharia, Dhanbad
AND
Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- None.

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 06/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub -section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/275/2003 -IR(C-I) dated 26/04/2004 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Bastacolla Area of M/s BCCL, Dhanbad and their workman through Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union, Hirapur, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the demand of the Bihar Colliery Kamgar Union from the management of Bastacolla Colliery of M/s BCCL for regularising Sri Seo Kumar Pswan as Fitter Helper w.e.f. 17.9.98 with protection of wages and for giving financial benefits under SLU since 1.1.96 is fair and justified? If so, to what relief is the concerned workman entitled?”

2. On receiving order no. L-20012/275/2003 -IR(C-I) dated 26/04/2004 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 36 of 2004 was registered on 14.05.2004 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

3. After receipt of the reference on 14.05.2004, this case was put up after a long gap on 26.11.2022 and regd. notices were issued to both the parties but neither the workman nor the management appeared before the Tribunal. Thereafter on 20.06.2025 Sri Rishi Raj Meena, Asst. Manager (L) for the management appeared after that he remained present but workman/union failed to appear.

4. On perusal of the entire case record it transpires that the workman/union never appeared before this Tribunal since the beginning which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.

5. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026

का.आ. 369.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधन के संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में **केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण - सह - श्रम न्यायालय, धनबाद-I** के पंचाट (संदर्भ संख्या 77/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को **09/03/2026** को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/585/2001-आईआर-(सीएम-1)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 13th March, 2026

S.O. 369.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 77/2006**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of CCL. and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**

[No. L-20012/585/2001- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 77/2006**Parties:**

Employers in relation to the management of Hendegir Colliery
of M/s. CCL, Hendegir, Ranchi

AND

Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- Sri D.K. Verma, Ld. Advocate.

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 06/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/585/2001-IR(CM-I) dated 30/08/2006 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Hendegir Colliery of M/s BCCL, Ranchi and their workman through President, N.C.O.E.A., Hendegir, Ranchi for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the demand of the NCOEA from the management of CCL, Hendegir Colliery to give employment to Sri. Jai Nandan Ganjhu the dependent of the deceased workman Shri Late Bahura Ganjhu as per the provision of NCWA-V is justified? If so, to what relief is the said dependent entitled?”

2. On receiving order no. L-20012/585/2001-IR(CM-I) dated 30/08/2006 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 77 of 2006 was registered on 15.09.2006 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

3. After receipt of the reference on 15.09.2006, this case record was put up after a long gap on 20.12.2021 and registered notices were sent to both the parties and both parties appeared on 14.03.2022 but thereafter workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared.

4. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since April, 2022 which shows that the workman/union has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.

5. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026

का.आ. 370.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण – सह – श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 72/2014) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/63/2014-आईआर-(सीएम-I)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 13th March, 2026

S.O. 370.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 72/2014) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026.

[No. L-20012/63/2014- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1, DHANBAD
In the matter of reference U/S 10 (1) (d) & (2A) of I.D. Act, 1947.

Reference Case No. 72/2014

Parties:

Employer in relation to the management of C.V. Area
 Of M/s. BCCL, Barakar, Burdwan
 AND
 Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
 Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- Sri S. Goswami, Asstt. Manager (L)
 For the workman :- None.

State : West Bengal.

Industry:-Coal
 Dated 06/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/63/2014 -IR(CM-I) dated 07/07/2014 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of C.V. Area of M/s. BCCL, Barakar, Burdwan and their workman through Secretary, Janta Mazdoor Sangh, Barakar, Burdwan for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the Management of C.V. Area of M/s BCCL in not regularizing of S/Sri Goutam Bouri and 19 others in the post of Mobile Crusher Mazdoor/feeder Breaker Mazdoor is fair and justified? To what relief the concerned workmen are entitled to?”

2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.
3. On receiving order no. L-20012/63/2014 -IR(CM-I) dated 07/07/2014 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 72 of 2014 was registered on 17.07.2014 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.
4. After receipt of the reference on 17.07.2014, this case was put up after a long gap on 17.01.2022 and regd. notices were issued to both the parties but neither the workman nor the management appeared before this Tribunal. Thereafter on 12.09.2025 Sri S.N. Ghosh, Advocate on behalf of the management appeared but workman/union again failed to appear and after that management appeared on certain dates. Today Sri S. Goswami, Asstt. Manager (L) for the management appeared and submitted that workman has not appeared since beginning in this case so case may be closed.
5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since beginning which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.
6. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026

का.आ. 371.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, धनबाद-I के

पंचाट (संदर्भ संख्या 76/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/580/2001-आईआर-(सीएम-1)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 13th March, 2026

S.O. 371.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 76/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of CCL. and their workmen received by the Central Government on 09/03/2026.

[No. L-20012/580/2001– IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 76/2006

Parties:

Employers in relation to the management of Hendegir Colliery

of M/s. CCL, Hendegir, Ranchi

AND

Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- Sri D.K. Verma, Ld. Advocate.

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 06/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/580/2001-IR(CM-I) dated 30/08/2006 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Hendegir Colliery of M/s BCCL, Ranchi and their workman through President, N.C.O.E.A., Hendegir, Ranchi for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the demand of the NCOEA from the management of CCL, Hendegir Colliery to give employment to Shri Babulal Munda the dependent of the deceased workman Shri Late Ledua Munda as per the provision of NCWA-V is justified? If so, to what relief is the said dependent entitled?”

2. On receiving order no. L-20012/580/2001-IR(CM-I) dated 30/08/2006 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 76 of 2006 was registered on 15.09.2006 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

3. After receipt of the reference on 15.09.2006, this case record was put up after a long gap on 20.12.2021 and registered notices were sent to both the parties and both parties appeared on 14.03.2022 but thereafter workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared.

4. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since April, 2022 which shows that the workman/union has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.

5. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026

का.आ. 372.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में **केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, धनबाद-I** के पंचाट (संदर्भ संख्या 167/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को **09/03/2026** को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/194/2001-आईआर-(सीएम-I)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 13th March, 2026

S.O. 372.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 167/2001**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**.

[No. L-20012/194/2001- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 167/2001

Parties:

Employer in relation to the management of Bastacolla Area
of M/s. BCCL, Jharia, Dhanbad

AND

Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- Sri Sambharant Pandey, Sr. Manager (HR)

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 06/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/194/2001 -IR(C-I) dated 11/07/2001 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Bastacolla Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through President, Bihar Colliery Kamgar Union, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“क्या प्रबंधन मै. भारत कोकिंग कोल लि. द्वारा श्रीमती पार्वती मोदीन के बी. आर. एस. एफ. के तहत सेवानिवृत्ति लेने पर उनके आश्रित पुत्र को नौकरी न देना न्यायायिक, कानूनी तथा तर्क दृष्टि से उचित है? यदि नहीं तो कर्मकार अथवा उनके आश्रित पुत्र किन लाभों के हकदार हैं?”

2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.

3. On receiving order no. L-20012/194/2001 -IR(C-I) dated 11/07/2001 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 167 of 2001 was registered on 09.08.2001 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

4. After service of notice, both parties appeared previously and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder. It further appears that after 2006 this case was put up after a long gap on 16.09.2021 and registered notices were issued to both the parties but workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma, Advocate on behalf of the management appeared. Thereafter on 08.08.2025 regd. notice was again issued to workman/union but he again failed to appear. Today Sri Sambharant Pandey, Sr. Manager (HR) on behalf of the management appeared and submitted that workman is not present since long so case may be closed.

5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since November 2021 which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.

6. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026

का.आ. 373.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एफसीआई के प्रबंधन के संबंध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में **केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, धनबाद-I** के पंचाट (संदर्भ संख्या 14/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को **09/03/2026** को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/117/2003-आईआर-(सीएम-I)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 13th March, 2026

S.O. 373.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 14/2004) of the **Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of **FCI** and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**.

[No. L-22012/117/2003- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 14/2004

Parties:

Employers in relation to the management of Food Corporation of India, Patna
AND
Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- None.

For the workman :- None.

State : Bihar .

Industry:-Food & Public Distribution
Dated 05/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-22012/117/2003 -IR(CM-II) dated 30/12/2003 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. Food Corporation of India, Patna and their workman through Additional State Secretary, Food Corporation of India Executive Staff Union, Patna for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Food Corporation of India in terminating the services of Sh. Radhey Shyam Sharma and others instead of regularizing their services against category IV is legal and justified? If not, to what relief the workmen are entitled?”

LIST OF WORKMEN

Sl. No.	Name of Concerned workmen	Date of Engagement	Date of Retrenchment
1.	Radhey Shyam Sharma	15.3.1986	01.01.1987
2.	Ram Pravesh Sharma	“	“
3.	Dilip Kumar	“	“
4.	Ashok Kumar	“	“
5.	Jainendra Kumar	“	“
6.	Subodh Kumar	“	“
7.	Shashi Kant	“	“
8.	Raju Kumar	“	“
9.	Sachidanand	“	“
10.	Niranjan Kumar	“	“
11.	Gorakhnath Rai	“	“
12.	Rakesh Kumar	“	“
13.	Amarendra Kumar	“	“
14.	Dinesh Rai	“	“
15.	Uma Shankar Kumar	“	“
16.	Vinod Kumar	“	“
17.	Mantoo Kumar	“	“
18.	Jitendra Kumar	“	“
19.	Umesh Singh	“	“
20.	Rajeshwar Sharma	“	“
21.	Som Nath	05.1.1987	16.11.87
22.	Ajeet Kumar Pandey	“	“
23.	Ranjay Kumar	“	“
24.	Sanjay Kumar	“	“
25.	Satyendra Kumar	“	“
26.	Sanjeet Kumar	“	“
27.	Pankaj Kumar	“	“

28.	Vijay Kumar	“	“
29.	Kaushlendra Ranjan	“	“
30.	Shyam Sunder Kumar	“	“
31.	Randhir Kumar	“	“
32.	Dhananjay Kumar	“	“
33.	Phuldeo Paswan	“	“
34.	Arun Kumar Singh	“	“
35.	Upendra Kumar	“	“
36.	Sunil Kumar	“	“
37.	Manoj Kumar	“	“
38.	Kundan Kumar	“	“
39.	Chhotu Kumar	01.12.87	24.3.89
40.	Lalit Kumar	“	“
41.	Sanjeev Kumar	“	“
42.	Shambhoo Kumar	“	“
43.	Amar Kumar	“	“
44.	Wakil Kumar	“	“
45.	Jeetendra Kumar	“	“
46.	Manoj Kumar	“	“
47.	Rajeshwar Singh	“	“
48.	Prabhat Kumar	“	“
49.	Neeraj Kumar	“	“
50.	Ameet Kumar	“	“
51.	Arun Kumar	“	“
52.	Deepak Kumar	“	“
53.	Manoranjan	“	“
54.	Prashant Kumar	“	“

2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.

3. On receiving order no. L-22012/117/2003 -IR(CM-II) dated 30/12/2003 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 14 of 2004 was registered on 04.02.2004 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

4. After receipt of the reference both the parties appeared and filed their authorities, W/S and subsequently rejoinder and after 01.09.2022 workman/union failed to appear before this Tribunal. However management appeared on certain dates.

5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union failed to appear before this Tribunal since October 2022 which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.

6. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026

का.आ. 374.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधन के संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 25/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/13/2007-आईआर-(सीएम-I)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 13th March, 2026

S.O. 374.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 25/2007**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**.

[No. L-20012/13/2007– IR (CM-I)]
JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 25/2007

Parties:

Employer in relation to the management of Bastacolla Area
Of M/s. BCCL, Jharia, Dhanbad
AND
Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey
Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- Sri S. Pandey, Sr. Manager (HR)
For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal
Dated 06/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No. L-20012/13/2007-IR(CM-I) dated 13/17.04.2007 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Bastacolla Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Executive Member, Bihar Colliery Kamgar Union, Bhuli, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Bastacolla Colliery of M/s BCCL in dismissing Shri Gura Manjhi, M/Loader from the services of the company w.e.f. 25.7.2005 is justified and legal? If not, to what relief is the concerned workman entitled?”

2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.

3. On receiving order no. L-20012/13/2007-IR(CM-I) dated 13/17.04.2007 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 25 of 2007 was registered on 01.05.2007 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

4. After receipt of the reference on 01.05.2007, this case was put up after a long gap on 06.01.2022 and regd. notices were issued to both the parties but neither the workman nor the management appeared before this Tribunal. Thereafter on 08.08.2025 and 12.12.2025 Sri N. Nath, O.S. Legal, H.Q and Sri Raju Kumar Mahto appeared on behalf of the management but workman/union again failed to appear. Today Sri S. Pandey, Sr. Manager (HR) for the management appeared and submitted that workman has not appeared since beginning in this case so case may be closed.

5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since beginning which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.

6. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026

का.आ. 375.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 20/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/99/2002-आईआर-(सीएम-1)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 13th March, 2026

S.O. 375.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 20/2003**) of the **Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**.

[No. L-20012/99/2002- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 20/2003

Parties:

Employer in relation to the management of Bastacolla Area

Of M/s. BCCL, Jharia, Dhanbad

AND

Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- Sri S. Pandey, Sr. Manager (HR)

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 06/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/99/2002-IR(C-I) dated 24/01/2003 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Bastacolla Area of M/s. BCCL, Dhanbad and their workman through Organizing Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of CIL;BCCL, CCO Dhansar, Bastacolla Area & Headquarters of BCCL;CMPDIL Ranchi, - R&D Construction Rajrappa; in not paying wages, annual increment and other dues to Shri S.K. Pandey, Sampling Assistant for the period from 20.4.94 to 6/99 is just, fair and legal? If not to what relief is the workman entitled? And ;

Whether the demand of RCMS, from the management of BCCL, Bastacolla Area for promotion of the workman from Cat.II to appropriate higher grade is just and fair? If so, to what relief is the workman entitled?”

2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.
3. On receiving order no. L-20012/99/2002-IR(C-I) dated 24/01/2003 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 20 of 2003 was registered on 05.02.2003 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.
4. After receipt of the reference on 05.02.2003, this case was put up after a long gap on 16.08.2021 and regd. notices were issued to both the parties but neither the workman nor the management appeared and notice of the workman/union returned with endorsement "Always Door Locked Addressee Left". Thereafter on 27.06.2025 Sri Rishi Raj Meena, Legal Inspector appeared on behalf of the management but workman/union again failed to appear. Thereafter management appeared on certain dates. Today Sri S. Pandey, Sr. Manager (HR) for the management appeared and submitted that workman has not appeared since beginning in this case so case may be closed.
5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since beginning which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.
6. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a "No Dispute Award" be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026

का.आ. 376.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बीसीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 09/2016) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/431/2001-आईआर-(सीएम-I)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 13th March, 2026

S.O. 376.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 09/2016**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of BCCL. and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**

[No. L-20012/431/2001- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD**

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 09/2016**Parties:**

Employers in relation to the management of Bastacolla Area
of M/s. BCCL, Jharia, Dhanbad

AND

Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- Sri Sambharant Pandey, Sr. Manager, H.R.

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 06/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/137/2015 -IR(CM-I) dated 15/12/2015 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Bastacolla Area of M/s. BCCL, Jharia, Dhanbad and their workman through Central Secretary, Jharkhand Colliery Mazdoor Union, Jeenagora, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the Management of Dobari Colliery under Bastacolla Area of M/s. BCCL in dismissing Shri Umesh Mohali, Ex-Miner Loader, Pers. No. 03039484 from the services on 21.02.2006 vide letter No. Dobari/09/056/143 of the company is fair and justified? To what relief the concerned workman is entitled to?”

2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.

3. On receiving order no. L-20012/137/2015 -IR(CM-I) dated 15/12/2015 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 09 of 2016 was registered on 04.01.2016 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

4. After receipt of the reference regd. notices were issued to both the parties and both parties appeared previously and filed their authorities and W/S but after 19.09.2019 workman/union failed to appear before this Tribunal. However management appeared on certain dates. Today Sri Sambharant Pandey, Sr. Manager (HR) appeared and submitted that workman has not appeared since October 2019, so case may be closed.

5. On perusal of the entire case record it transpires that the workman never appeared before this Tribunal since October 2019 which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.

6. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026

का.आ. 377.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीसीएल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 45/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/533/2001-आईआर-(सीएम-I)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 13th March, 2026

S.O. 377.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 45/2002**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of CCL. and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**.

[No. L-20012/533/2001– IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 45/2002

Parties:

Employers in relation to the management of Giridih Area
Of M/s. CCL, Giridih

AND

Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- None.

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Coal

Dated 04/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-20012/533/2001 -IR(C-I) dated 01/03/2002 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Giridih Area of M/s. CCL, Giridih and their workman through Regional Secretary, United Coal Workers Union, Giridih for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of CCL in refusing to regularize Sri Gautam Kumar Pandey, Cat-I worker as Helper in Excvn cadre w.e.f. 1993 and thereafter as EP fitter/Drill Operator is fair and justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled and from what date ?”

2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.

3. On receiving order no. L-20012/533/2001- IR(C-I) dated 01/03/2002 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 45 of 2002 was registered on 21.03.2002 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

4. After receipt of the reference on 21.03.2002, this case was put up after a long gap on 02.08.2021 and regd. notices were issued to both the parties but workman/union failed to appear before this Tribunal. However Sri D.K. Verma, Ld. Advocate on behalf of the management appeared.

5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since 2021 which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.

6. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026

का.आ. 378.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के प्रबंधन के संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 11/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09/03/2026 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/517/2002-आईआर-(सीएम-1)]

जयदीप यादव, उप निदेशक

New Delhi, the 13th March, 2026

S.O. 378.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (**Ref. No. 11/2003**) of **the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I** as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the Management of **Damodar Vallery Corporation** and **their workmen** received by the Central Government on **09/03/2026**

[No. L-20012/517/2002- IR (CM-I)]

JAIDEEP YADAV, Dy. Director

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD**

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 11/2003**Parties:**

Employers in relation to the management of Damodar Valley Corporation, Kolkata

AND

Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- None.

For the workman :- None.

State : Jharkhand.

Industry:-Power

Dated 05/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-42012/51/2002 -IR(CM-II) dated 06/01/2003 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Damodar Valley Corporation, Kolkata and their workman through Secretary, United Coal Workers Union, Bokaro Thermal, Bokaro for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of D.V.C. in not providing employment on regular basis to the 11 contractor’s workers (list enclosed) is legal and justified? If not, to what relief they are entitled to?”

List of workmen

क्रम स.	नाम	पिता/पति का नाम	इ. पी. एफ. न.
1.	मदन झा	नन्द झा	5160
2.	रविलोचन बनर्जी	ए. के. बनर्जी	5071
3.	पवन कुमार झा	ए. एन. झा.	4350
4.	श्रवण कुमार झा	ए. एन. झा.	4976
5.	इंद्रकांत राय	ए. राय	4784
6.	राजू घाँषी	दुलिया घाँषी	5126
7.	चंदू राम	तपसी राम	5083
8.	श्रीमती मणि देवी	गुलेश्वर उराँव	5131
9.	बैधनाथ प्रसाद	जोधी प्रसाद	5078
10.	राजेन्द्र प्रसाद सिंह	डी. एन. सिंह	4756
11.	विकलांग	रोस्टर के आधार पर	

2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.

3. On receiving order no. L-42012/51/2002- IR(CM-II) dated 06/01/2003 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 11 of 2003 was registered on 21.01.2003 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

4. After receipt of the reference on 21.01.2003, this case was put up after a long gap on 17.09.2021 and regd. notices were issued to both the parties and Sri Somnath Chakraborty, Advocate appeared on behalf of the management on 06.12.2021 but workman/union failed to appear before this Tribunal. After that management also failed to appear. Thereafter on 29.08.2025 regd. notices were again issued to both the parties and Sri Kaushal Kumar, Advocate for the management appeared but workman/union again failed to appear.

5. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union never appeared before this Tribunal since beginning which shows that he has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.

6. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026

का.आ. 379.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र, संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नागपुर के पंचाट (48/2017-18) प्रकाशित करती है।

[सं. एल-12011/39/2017-आई आर (बी-1)]

सलोनी, उप निदेशक

New Delhi, the 16th March, 2026

S.O. 379.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. 48/2017-18) of the *Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court Nagpur* as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India their workmen.

[No. L-12011/39/2017- IR(B-I)]

SALONI, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE SHRI SHIV SHANKER PRASAD PRESIDING OFFICER,

CGIT-CUM-LABOUR COURT, NAGPUR

Case No.CGIT/NGP/48/2017-18

Date:06.02.2026.

Party No.1:

The Chief General Manager,
State Bank of India, P & HRD, IR Cell,
Local Head Office, Synergy, C-6, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai - 400051
The Dy. General Manager,
State Bank of India, Zonal Office, Zone-I,
S.V. Patel Marg, Kingsway,
Nagpur - 440001

V/s.

Party No.2:

The Dy. General Manager,
State Bank Karmachari Sena, (Nagpur Module),
C/o State Bank of India, Ramdaspath Branch,
Nagpur

AWARD

(Dated:6thFebruary, 2026)

In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) ("the Act" in short), the Central Government has referred the industrial dispute between the employers, in relation to the management of State Bank of India and the Union of State Bank Karmachari Sena, (Nagpur Module), for adjudication, as per **No. L-12011/39/2017 (IR(B-I)) dated 01.02.2018**, with the following schedule: -

"Whether action of the management of State Bank of India, Local Head Office, Mumbai through its Chief General Manager and State Bank of India Zonal Office, Zone-I, Nagpur Through its Dy. General Manager to implement the transfers under redeployment policy without taking into consideration the data of branch wise access/ shortage staff along with the criteria adopted to arrive at such figure as well as the appointment of the new recruits and merger of associate banks in State Bank of India is fair, just or legal? If not, to what relief the concerned Union is entitled to? And what are the other directions necessary in the matter?"

2. Case is called out. Learned counsel for the respondent Shri. Dadu Sachadeva is present before the court but no one is present on behalf of petitioner despite service of notice. On the previous date learned counsel for the Party No. 2, Mr. Marpakwar has filed a pursis wherein he has mentioned that despite repeated attempts to contact by a phone calls and latter to client he has failed to provide necessary instructions to proceed further in the present matter. In these circumstances, he has withdrawn his power on the previous date. From perusal of record, it is apparent that this reference has been received to this court on 16.02.2018. Although Statement of Claim and Written Statement as well as rejoinder have been filed by the parties respectively but no evidence has been filed by the petitioner to prove his case. Therefore, it appears that petitioner is not interested to contest the case further more. No other evidence has been filed by the petitioner to prove the contents of the claim. Claim of the petitioner is not proved. So, it is closed.

Hence, it is ordered.

ORDER

“The action of the management of State Bank of India, Local Head Office, Mumbai through its Chief General Manager and State Bank of India Zonal Office, Zone-I, Nagpur Through its Dy. General Manager to implement the transfers under redeployment policy without taking into consideration the data of branch wise access/ shortage staff along with the criteria adopted to arrive at such figure as well as the appointment of the new recruits and merger of associate banks in State Bank of India is fair, just or legal. The union is not entitled to any relief.”

Justice (Retd.) SHIV SHANKER PRASAD, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026

का.आ. 380.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन, संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नागपुर के पंचाट (49/2017-18) प्रकाशित करती है।

[सं. एल-12011/37/2017-आईआर-(बी-1)]

सलोनी, उप निदेशक

New Delhi, the 16th March, 2026

S.O. 380.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. 49/2017-18) of the *Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court Nagpur* as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India their workmen.

[No. L-12011/37/2017- IR(B-I)]

SALONI, Dy. Director

ANNEXURE**BEFORE SHRI SHIV SHANKER PRASAD PRESIDING OFFICER,****CGIT-CUM-LABOUR COURT, NAGPUR**

Case No.CGIT/NGP/49/2017-18

Date:03.02.2026

Party No.1:

- 1) The Dy. General Manager,
State Bank of India, Zone -I,
Zonal Office, Kingsway, S.V. Patel Marg,
Nagpur – 440001
- 2) The Chief Manager, State Bank of India,
Kamptee Branch, Distt. Kamptee,
Nagpur – 441002

V/s.

Party No.2:

The Dy. General Secretary State Bank Karmachari Sena
(Nagpur Module) C/o. State Bank of India,
Nagpur Main Branch, SV Patel Marg,
Kingsway, Nagpur - 440001.

AWARD

(Dated: 3rd February, 2026)

In exercise of the powers conferred by Clause (d) of sub-section (1) and Sub-section 2(A) of Section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) ("the Act" in short), the Central Government has referred the industrial dispute between the employers, in relation to the management of State Bank of India through its Dy. General Manager, Nagpur and Chief Manager, Kamptee Branch and the applicant, Shri. R. P. Shukla for adjudication No. L-12011/37/2017 (IR(B-I)) dt. 01.02.2018, with the following issues framed: -

"Whether the action of the management of State Bank of India through its Dy. General Manager, Nagpur and Chief Manager Kamptee Branch in treating the leave period i.e. 27.06.2014 to 09.07.2014 as unauthorized absent from duty with loss of pay for the said period in respect of Shri. R. P. Shukla, Bank Guard, SBI Kamptee specifically when the disputant workman was applied for leave on 20.06.2014 and subsequently leave was extended on medical ground is proper and legal? If not, what relief to the workman is entitled to?"

2. On receipt of the reference, parties were noticed to file their respective Statement of Claim and Written Statement. In response to which, the workman Shri. R. P. Shukla filed the Statement of Claim and the management of State Bank of India ("Party No. 1" in short) filed the Written Statement. Petitioner filed his rejoinder and evidence on affidavit.

Meanwhile, on 23.12.2025 the Hon'ble court opined that, the matter was not serious in nature and their being minor involvement of funds which can be compromised out of the court. Both the parties agreed and arrived on a compromise. A letter of compromise duly signed by both the parties submitted on 07.01.2026. Thus, the case is taken on today's board in special campaign and considered for passing the award.

Both parties have settled the dispute amicably in terms and conditions mentioned in the memo of compromise signed by both the parties.

Hence, it is ordered.

ORDER

"The reference is answered in favor of the workmen in terms of the settlement mentioned in the memo of compromise. The memo of settlement dt. 07.01.2026 is made part of the award."

Justice (Retd.) SHIV SHANKER PRASAD, Presiding Officer

Tribunal

BEFORE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NAGPUR.**F.F. 07.1.2026****CGIT Reference Case No. CGIT/NGP/ 61/2045****THE CHIEF GENERAL MANAGER SBI & 2****Vs.****THE DEPUTY GENERAL SBI Karamchari Sena (R.P. Shukla)****TERMS OF COMPROMISE**

That the parties have settled the matter out of court on the following terms :

01. That as per the workman (Employee number 00441091) he joined the Branch as Security Guard, on 07.07.2013. He applied for earned leave of 20 days from 19.08.2013 to 07.09.2013, but the Bank sanction only 5 days due to cogent reasons, on 19.08.2013. Absence of the workman was treated as leave without pay i.e loss of pay of 15 days and deducted Rs. 17,825/ for not allowing encashment of leave. Being aggrieved by the Bank action the workman has approached this Hon'ble Tribunal claiming Rs. 17,825/.

Recd. copy
on 7/1/26

[Signature]
(R.A. Jain, Adv)

02. That as per the Bank, the leave was refused due to shortage of Security Guards and other security reasons. The leave can not be claimed as of right. The workman did not suffered any loss but gained. The leave which was not deducted from his leave credit account was paid at the time of retirement which is more than what the workman claims to have lost. The calculation are incorrect.

03. At the time of retirement the workman was having credit of
 earned leave of 240 days
 and received Rs. 4,82,728.08
 15 days amount comes to
 4,82,728.08 divided by 240 x 15= Rs. 0,30,170.49
 + Paid today by Demand Draft Rs. 0,10,000.00
 No.807909 dated 24.12.2025
 favoring R.P. Shukla(the workman).

Total Paid Rs. 40,170.49

Against claim of Rs. 17,825.00
 Received amount of Rs. 40,170.49
 Thus received excess amount than
 claimed Rs. 22,345.49

Hence, workman is not entitled for any relief.

03. That during the trial it was opined by this Hon'ble Tribunal that the looking to the nature of the matter being non serious and there being minor involvement of funds it may be compromised out of court.

04. That in view of above facts the Bank has paid Rs. 10,000/ by DD No.807909 dated 24.12.2025 favoring R.P. Shukla(workman), on account of full and final settlement of all claims against all reliefs claimed in the case, which hs been accepted by the workman voluntarily and willingly.

05. That workman shall not claim anything extra on any account in future.

Workman

C.F. Workman

Nagpur

DATED: 07.1. 2026

For State Bank of India,

C.F. State Bank of India

**BEFORE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL,
NAGPUR.****F.F. 07.1.2026****CGIT Reference Case No. CGIT/NGP/ 61/2045****THE CGM SBI & 2 Vs. DGS SBI Karamchari Sena (R.P. Shukla)****DEMAND DRAFT DELIVERED TO THE WORKMAN**

**That in terms of compromise in the above said case
the Bank has delivered the following demand draft to the workman
Shri. R.P. Shukla, today.**

जारी करने वाली भारतीय स्टेट बैंक
Issuing Bank: STATE BANK OF INDIA NAGPUR
कोड क्र./CODE No: 00400
Tel No.

मांगे जानेपर R.P. SHUKLA
ON DEMAND PAY
Ten Thousand Only
रुपये RUPEES

मांगे जापट
DEMAND DRAFT

Key: WIJDUV
Sr. No: 183782

2 4 1 2 2 0 2 5
D D M M Y Y Y Y

या उनके आदेश पर
OR ORDER

अदा करें ₹ 10000.00

IOI 000546807909
Name of Applicant
TRANSFER FROM G/L

Key: WIJDUV
Sr. No: 183782
AMOUNT BELOW 10001(0/5)

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH: NAGPUR
कोड क्र. /CODE No: 00432

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

₹ 1,50,000/- एवं अधिक के लिखत हो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

⑈807909⑈ 000002000⑈ 000546⑈ 16

**Received the above said original
Demand Draft as full and final
settlement of all claims in the above
said as per compromise.**

(R.P. Shukla)

**Nagpur
Date 07.01.2026**

C.F.SBI

*Recd. DD 807909
under protest.*

Shukla
C.F.SBI

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026

का.आ. 381.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र, संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नागपुर के पंचाट (61/2014-15) प्रकाशित करती है।

[सं. एल-12011/98/2014-आई आर (बी-1)]

सलोनी, उप निदेशक

New Delhi, the 16th March, 2026

S.O. 381.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref.61/2014-15) of the *Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court Nagpur* as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of State Bank of India their workmen.

[No. L-12011/98/2014- IR(B-I)]

SALONI, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE SHRI SHIV SHANKER PRASAD PRESIDING OFFICER,

CGIT-CUM-LABOUR COURT, NAGPUR

Case No.CGIT/NGP/61/2014-15

Date:03.02.2026.

Party No.1:

- 1) The Assistant General Manager,
State Bank of India, Region-III, Zonal-I,
Zonal Office, Nagpur, Kingsway,
S.V. Patel Marg, Nagpur - 440001
- 2) The Chief Manager, State Bank of India,
Kamptee Branch, Kamptee,
Distt. Nagpur – 441002
- 3) The Chief General Manager,
State Bank of India, Local Head Office,
Synergy, C-6 Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400051.

V/s.

Party No.2:

The Dy. General Secretary State Bank Karmachari Sena
(Nagpur Module) C/o. State Bank of India,
Nagpur Main Branch, SV Patel Marg,
Kingsway, Nagpur- 440001.

AWARD

(Dated:3rd February, 2026)

In exercise of the powers conferred by Clause (d) of sub-section (1) and Sub-section 2(A) of Section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) ("the Act" in short), the Central Government has referred the industrial dispute between the employers, in relation to the management of State Bank of India through its Dy. General Manager, Nagpur and Chief Manager, Kamptee Branch and the applicant, Shri. R. P. Shukla for adjudication No. L-12011/98/2014 (IR(B-I)) dt.22.01.2025, with the following issues framed: -

"Whether the action of the management of State Bank Karmachari Sena (Nagpur Module) against the management of State Bank of India deducting an amount of Rs. 17,825/- towards loss of pay and not allowing encashment of 15 days privilege leave of Shri. R. P. Shukla, Armed Guard, SBI Branch Kamptee is legal, just and proper? If not, to what relief to the workman concerned is entitled to?"

2. On receipt of the reference, parties were noticed to file their respective Statement of Claim and Written Statement. In response to which, the workman Shri. R. P. Shukla filed the Statement of Claim and the management of State Bank of India ("Party No. 1" in short) filed the Written Statement. Petitioner filed evidence on affidavit and he was cross-examined by the Respondent.

Meanwhile, on 07.11.2025 the Hon'ble court opined that, the matter was not serious in nature and their being minor involvement of funds which can be compromised out of the court. Both the parties agreed and arrived on a compromise. A letter of compromise duly signed by both the parties submitted on 07.01.2026. Thus, the case is taken on today's board under special campaign and considered for passing the award.

Both parties have settled the dispute amicably in terms and conditions mentioned in the memo of compromise.

Hence, it is ordered.

ORDER

"The reference is answered in favor of the workmen in terms of the settlement mentioned in the memo of compromise. The memo of settlement dt. 07.01.2026 is made part of the award."

Justice (Retd.) SHIV SHANKER PRASAD, Presiding Officer

Tribunal

BEFORE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NAGPUR.

F.F. 07.1.2026

CGIT Reference Case No. CGIT/NGP/ 61/2045

THE CHIEF GENERAL MANAGER SBI & 2

Vs.

THE DEPUTY GENERAL SBI Karamchari Sena (R.P. Shukla)

TERMS OF COMPROMISE

That the parties have settled the matter out of court on the following terms :

01. That as per the workman (Employee number 00441091) he joined the Branch as Security Guard, on 07.07.2013. He applied for earned leave of 20 days from 19.08.2013 to 07.09.2013, but the Bank sanction only 5 days due to cogent reasons, on 19.08.2013. Absence of the workman was treated as leave without pay i.e loss of pay of 15 days and deducted Rs. 17,825/ for not allowing encashment of leave. Being aggrieved by the Bank action the workman has approached this Hon'ble Tribunal claiming Rs. 17,825/.

02. That as per the Bank, the leave was refused due to shortage of Security Guards and other security reasons. The leave can not be claimed as of right. The workman did not suffered any loss but gained. The leave which was not deducted from his leave credit account was paid at the time of retirement which is more than what the workman claims to have lost. The calculation are incorrect.

*Recd. copy
on 7/1/26*

*[Signature]
(R.A. Jain, Asst.)*

03. At the time of retirement the workman was having credit of
 earned leave of 240 days
 and received Rs. 4,82,728.08
 15 days amount comes to
 4,82,728.08 divided by $240 \times 15 =$ Rs. 0,30,170.49
 + Paid today by Demand Draft Rs. 0,10,000.00
 No.807909 dated 24.12.2025
 favoring R.P. Shukla(the workman).

Total Paid Rs. 40,170.49

Against claim of Rs. 17,825.00
 Received amount of Rs. 40,170.49
 Thus received excess amount than
 claimed Rs. 22,345.49

Hence, workman is not entitled for any relief.

03. That during the trial it was opined by this Hon'ble Tribunal that the looking to the nature of the matter being non serious and there being minor involvement of funds it may be compromised out of court.

04. That in view of above facts the Bank has paid Rs. 10,000/ by DD No.807909 dated 24.12.2025 favoring R.P. Shukla(workman), on account of full and final settlement of all claims against all reliefs claimed in the case, which hs been accepted by the workman voluntarily and willingly.

05. That workman shall not claim anything extra on any account in future.

Workman

C.F. Workman

Nagpur

DATED: 07.1. 2026

For State Bank of India,

C.F. State Bank of India

**BEFORE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL,
NAGPUR.****F.F. 07.1.2026****CGIT Reference Case No. CGIT/NGP/ 61/2045****THE CGM SBI & 2 Vs. DGS SBI Karamchari Sena (R.P. Shukla)****DEMAND DRAFT DELIVERED TO THE WORKMAN**

**That in terms of compromise in the above said case
the Bank has delivered the following demand draft to the workman
Shri. R.P. Shukla, today.**

जारी करने वाली संस्था स्टेट बैंक
Issuing Agency STATE BANK OF INDIA NAGPUR
कोड क्र./CODE No: 00400
Tel No.

मांगे जानेपर R.P. SHUKLA
ON DEMAND PAY
Ten Thousand Only
रुपये RUPEES

मांगड़ाफ्ट
DEMAND DRAFT

Key: WIJDUV
Sr. No: 183782

2 4 1 2 2 0 2 5
D D M M Y Y Y Y

8
या उनके आदेश पर
OR ORDER

अदा करें ₹ 10000.00

IOI 000546807909
Name of Applicant
Key: WIJDUV
Sr. No: 183782
TRANSFER FROM G7L
AMOUNT BELOW 10001(0/5)

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH: NAGPUR
कोड क्र./CODE No: 00432

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 माहों के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

₹ 1,50,000/- एवं अधिक के लिखत में अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

⑈807909⑈ 000002000⑈ 000546⑈ 16

**Received the above said original
Demand Draft as full and final
settlement of all claims in the above
said as per compromise.**

(R.P. Shukla)
Nagpur
Date 07.01.2026
C.F.SBI

*Recd. DD 807909
under protest*

Shukla
C.F.SBI

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026

का.आ. 382.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन, संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं 1 धनबाद के पंचाट (96/2006) प्रकाशित करती है।

[सं. एल-12011/80/2006-आईआर-(बी-II)]

सलोनी, उप निदेशक

New Delhi, the 16th March, 2026

S.O. 382.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. 96/2006) of the *Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No. 1,Dhanbad* as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Bank of India their workmen.

[No. L-12011/80/2006- IR(B-II)]

SALONI, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 96/2006

Parties:

Employers in relation to the management of Bank of India, Kerkend
Branch, Kusunda, Dhanbad

AND

Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- None.

For the workman :- Sri Pradeep Kr. Singh, Secretary

State : Jharkhand.

Industry:-Bank

Dated 06/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-12011/80/2006-IR(B-II) dated 13/11/2006 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Bank of India, Kerkend Branch, Dhanbad and their workman through Working President, Jharkhand Colliery Mazdoor Union, Dhanbad for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the claim of employment of Shri Kamakhya Narayan Tiwari that he was engaged by the management of Bank of India as a Peon during the period from September, 2001 to 21.09.2004 is correct, If so, whether the action of the management in terminating him from service thereafter is legal and justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled?”

2. On receiving order no. L-12011/80/2006-IR(B-II) dated 13/11/2006 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 96 of 2006 was registered on 28.11.2006 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

3. After receipt of the reference on 28.11.2006, this case record was put up after a long gap on 20.12.2021 and registered notices were sent to both the parties and on 02.06.2022 and 14.07.2022 Sri Sadhu Sharan Pd., Representative on behalf of the workman appeared but management failed to appear thereafter workman also failed to appear before this Tribunal. Later on 22.08.2025 and 24.10.2025 Sri Pradeep Kumar Singh, Secretary of the union appeared and submitted that concerned workman is not interested to contest this case so case may be closed.

4. On perusal of the entire case record it transpires that workman/union has lost his interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.

5. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026

का.आ. 383.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार केनरा बैंक के प्रबंधतंत्र, संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं 1 धनबाद के पंचाट (105/2003) प्रकाशित करती है।

[सं. एल-20012/105/2003-आईआर-(बी-II)]

सलोनी, उप निदेशक

New Delhi, the 16th March, 2026

S.O. 383.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. 105/2003) of the *Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No. 1,Dhanbad* as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Canara Bank their workmen.

[No. L-12012/105/2003- IR(B-II)]

SALONI, Dy. Director

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1,DHANBAD

In the matter of reference U/S 10 (1) (d)& (2A) of I.D.Act. 1947.

Reference Case No. 105/2003

Parties:

Employer in relation to the management of Canara Bank, Patna

AND

Their Workman

Present: Shri Sachindra Kumar Pandey

Presiding Officer

Appearances:

For the Employers :- None.

For the workman :- None.

State : Bihar.

Industry:-Bank

Dated 06/02/2026

AWARD.

In exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) and sub –section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government Of India through the Ministry of Labour, vide its Order No.L-12012/105/2003-IR(B-II) dated 18/09/2003 has been pleased to refer the following dispute between the employer i.e. management of Canara Bank, Patna and their workman Smt. Asha Devi for adjudication by this Tribunal:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Canara Bank in terminating the service of Smt. Asha Devi is legal and justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?”

2. This case is taken through Special Campaign organized by Ministry of Labour & Employment, Govt. of India for disposal of pending cases.

3. On receiving order no. L-12012/105/2003-IR(B-II) dated 18/09/2003 Government of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, Reference case no. 105 of 2003 was registered on 07/13.10.2003 and thereafter the notices were sent to the parties with a direction to appear and submit their written statements along with relevant documents and witnesses in support of their claims.

4. After receipt of the reference on 07/13.10.2003, this case was put up after a long gap on 17.09.2021 and regd. notices were issued to both the parties but neither the workman nor the management appeared before this Tribunal and notice of the workman/union returned with endorsement “प्राप्तकर्ता का पता नहीं चलने के कारण वापस”.

5. On perusal of the entire case record it transpires that both the parties never appeared before this Tribunal since beginning which shows that both the parties have lost their interest in this case and therefore, for the ends of justice, this case deserves to be dismissed for non prosecution.

6. Hence,

ORDERED

that this case is hereby dismissed for non prosecution and a “No Dispute Award” be drawn up in respect of the above reference case. Let the copies of Award in duplicate be sent to the Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi for information and notification.

SACHINDRA KUMAR PANDEY, Presiding Officer